सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 167, नई दिल्ली, सोमवार 25 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दृढ़ता है...

03 दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, एस.बी.के. सिंह को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी

06 एमबीबीएस का विकल्प

08 स्तनपान सप्ताह: संकोच तोड़ने और सम्मान जोड़ने का अभियान

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में,

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में पीईएफआई (PEFI), युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौरव के लिए सवारी।

प्रयागराज से दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए - 24 अगस्त से 31 अगस्त तक,

अमर हॉकी आइकन मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।

आइये विरासत के लिए आगे बढ़ें, आइये भारत के लिए आगे बढ़ें।

हम 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर ग्रैंड फिनाले के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं... हमसे जुड़ें

Ride for National pride under the aegis PEFI, Ministry of Youth Affairs & Sports, GOI on the occasion of the celebration of Rashtriya Khel Mahotsav 2025.

Prayagraj to Delhi via Kanpur, Jhansi, Gwalior & Agra – 24th August to 31st August, to pay tributes to immortal Hockey icon Maj. Dhyan Chand ji.

Let's ride for Legacy, let's ride for India.

We are reaching Delhi on 31st August at 0730 am Maj. Dhyan Chand Stadium, India Gate for grand finale...join us

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है–
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

स्पेशल ई-रिक्शा संचालन हेतु डीएल दिया जाता है जबकि अधिकांश ई-रिक्शा संचालकों के पास डीएल है ही नहीं। कौन जिम्मेदार ?

संजय बाटला

क्या आला अधिकारी (परिवहन आयुक्त) परिवहन विभाग दिल्ली की जानकारी में है की ई रिक्शा पंजीकरण के लिए मालिक के नाम पर ही चालक लाइसेंस और बेज का होना अति आवश्यक है और एक व्यक्ति के नाम एक ही ई रिक्शा पंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि ई रिक्शा खरीदने वाले को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी देने का आदेश है।

दिल्ली की सड़को पर चलने वाले अधिकतर ई रिक्शा चालकों के पास चालक लाइसेंस ही उपलब्ध नहीं हैं और अगर लाइसेंस नहीं है तो बेज होने का तो सवाल ही नहीं उठता जो की सार्वजनिक सवारी वाहन चलाने के लिए अति अनिवार्य दस्तावेज है।

आप की जानकारी हेतु बता दें वाहन डाटा बेस के अनुसार दिल्ली में ऐसे कई व्यक्तियों के नाम उपलब्ध है जिनके नामों पर अनगिनत रिक्शा पंजीकृत है। अब सवाल यह उठता हैं की एक व्यक्ति एक से ज्यादा ई रिक्शा चला कैसे सकता है और कानून के अनुसार भी एक व्यक्ति के नाम पर मात्र एक ई रिक्शा पंजीकरण होना निश्चित किया गया था तो

1. एक ही आदमी के नाम पर एक से अधिक ई रिक्शे पंजीकृत हुए कैसे ?

2. एक वाहन लाइसेंस पर अनगिनत पंजीकृत ई रिक्शा कैसे चल सकते है, अर्थात दिल्ली की सड़को पर बिना लाइसेंस के चलने वाले ई रिक्शे का मुख्य कारण स्वयं परिवहन विभाग के अधिकारी हैं।

3. ई-रिक्शा सवारियों के लिए हैं, किन्तु लोग इनमें सामग्री भरकर चला रहे हैं।

4. बिना पंजीकरण का ई रिक्शा या कोई भी वाहन सड़को पर गतिविधि नहीं कर सकता और इसके प्रति दिल्ली उच्च न्यायालय का भी आदेश जारी है पर दिल्ली की सड़को पर पंजीकृत से अधिक मात्रा में बिना पंजीकृत वाहन व्यवसायिक गतिविधि में शामिल है।

5. बिना मान्य वाहन जांच प्रमाण पत्र के वाहन व्यावसायिक गतिविधियों में चलना एमवी एक्ट के अनुसार मना है पर दिल्ली की सड़को पर ऐसे वाहन बेखौफ व्यवसायिक गतिविधि में चलते हुए पाए जाते है

6. बिना वैलिड वाहन इंश्योरेंस के सड़को पर वाहन व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ई रिक्शा के चलने के लिए प्रतिबंधित सड़को पर बेखौफ चलते नजर आते है।

क्या कारण हैं की दिल्ली की सड़को पर निजी नंबरों के, बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनो के साथ

बिना वैलिड एमवी एक्ट के अनुसार अनिवार्य दस्तावेजों और बिना पंजीकृत वाहन हर गली कूचे और सड़को पर बेखौफ दौड़ते नजर आ रहे हैं पर उन के खिलाफ मोटर वाहन नियम के अनुसार कार्यवाही करने को कोई तैयार नहीं ?

क्या दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और प्रवर्तन शाखा वालो पर कोई राजनीतिक दबाव है या परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश है की इन पर कार्यवाही नहीं की जाए।

या दिल्ली यातायात पुलिस और प्रवर्तन शाखा परिवहन विभाग के अधिकारी की नजर में ना तो मीटर वाहन नियमों, ना ही उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों और ना ही परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का कोई डर है जो यह सभी को दरकिनार कर सिर्फ गिनती दिखाने के लिए छूट मुट कमियों वाले वाहनों के चालान काट कर अपनी ड्यूटी को दिखा कर दिल्ली की सड़को पर अवैध वाहनों को बेखौफ चलवाने में मददगार बन कर जनता के जीवन को असुरक्षित बना रहे है और सब कुछ जानते और देखते हुए भी आला अधिकारियों के अतिरिक्त दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल दिल्ली और उच्च न्यायालय है चुप।

क्या दिल्ली की सड़को पर चलने वाले भारत एवम्विदेशी पर्यटक के जान माल की कोई कीमत इनकी नजर में नहीं, बड़ा सवाल ?

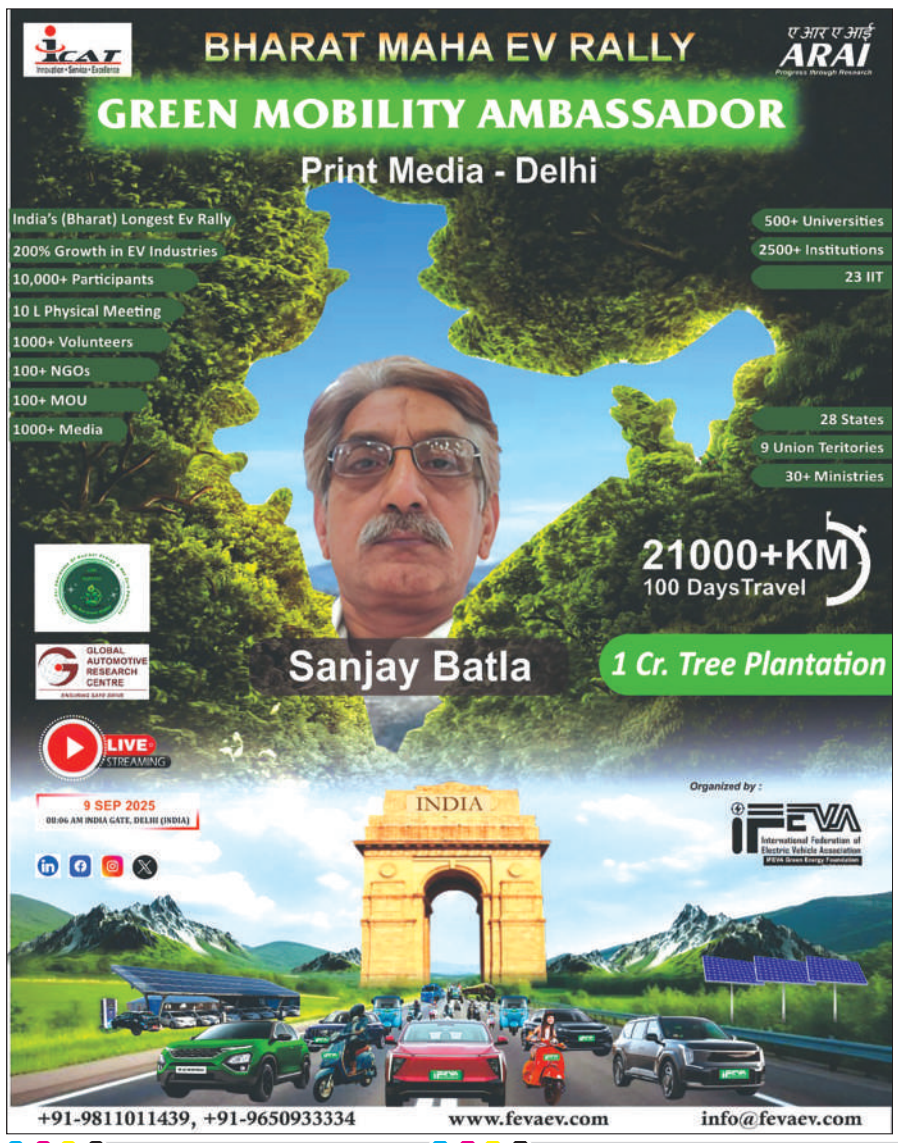

'दिल्ली में सफाई अभियान महीना' भाजपा सरकार का दिखावटी विकास कार्य,

दिल्ली सरकार का दावा धराशाही वो भी दिल्ली में जीते हुए भाजपा के निगम पार्षदों और विधायकों के कारण

संजय बाटला

नई दिल्ली। जिस क्षेत्रों में विधायक गलती से जनता की परेशानी को देखते हुए सफाई या नाली सफाई करवाना चाहते है वहां निगम पार्षद और उसके पारिवारिक सदस्य अपने पद और पद की ताकत का दुरूपयोग करते हुए काम रुकवा रहे हैं। कैसा है यह भाजपा का प्रशासन और भाजपा के आला कमान का मान,

दिल्ली आज जहां सांसद, विधायक और निगम पार्षद भाजपा के है वहीं जनता की सबसे अधिक दुर्गति हो रही हैं आखिर क्यों ?

भारत सरकारः- भाजपा
दिल्ली सरकारः- भाजपा
दिल्ली नगर निगमः- भाजपा
दिल्ली मेयरः- भाजपा
दिल्ली उपराज्यपालः- भाजपा

फिर भी जनता की दुर्गति और दुर्गती करने वाले जीते हुए विधायक और निगम पार्षद

क्यों चुप है भाजपा दिल्ली के आला है कोई जवाब ?

दिल्ली की जनता किस दर पर जाकर करे शिकायत है क्या कोई जवाब

और सबसे बड़ी देखने योग्य बात इस सब का फायदा उठा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, एसडीएम और क्षेत्र डीसी

दिल्ली के उपराज्यपाल चुप क्यों ?

दिल्ली की मुख्यमंत्री चुप क्यों ?

दिल्ली में जगह जगह गंदगी के ढेर वो भी सिर्फ सफाई ना होने देने के कारण

दिल्ली में सीवर, नालिया जाम वो भी सिर्फ सफाई ना होने देने के कारण

तो निगम पार्षद और विधायकों को इस काम के लिए मिलने वाला फंड कहा खर्च हो रहा हैं सिर्फ कागजों में या हवा में, बड़ा सवाल ?

जनता भाजपा दिल्ली, दिल्ली उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दिल्ली से चाहती हैं जवाब, है कोई जो जनता के समक्ष आकर दे सकता है जवाब?

दिल्ली में किसी भी कालोनी, किसी भी पार्क की जांच करवा ली जाए, कही भी सफाई या नाली, सीवर खुले दिखा दें खुला दावा

शहीद भगत सिंह कालोनी में निगम पार्षद के भेद भाव से जनता में भारी रोष

पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग वार्ड के शहीद भगत सिंह कालोनी जहां जनता और क्षेत्रिय समाज सेवा में शामिल संस्थाओं द्वारा सफाई के लिए आवाज उठाई जा रही है और उसके बावजूद सफाई नहीं की जाने दी जा रही वहां की निगम पार्षद और उसके पारिवारिक सदस्यों की जिद के कारण में शुक्रवार को अचानक निगम पार्षद, उसका पति आनन्द त्यागी, कुछ निगम कर्मचारी और एक अन्य अधिकारी जिसे डीसी बताया गया अचानक बिना सुचना के अचानक कुछ दौरा करते पाए गए और दौरा समाप्त भी नहीं हुआ होगा तभी एक एमसीडी कर्मचारी द्वारा दुकानदारों और कुछ को फोन कर के धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे दुकान के आगे टिन जो शेड लगे हैं उन्हें अभी तोड़ दिया जायेगा और यह आदेश हमारे हमारे साथ क्षेत्रीय

डी सी साहब का है।

कालोनी के सामाजिक कार्यकर्ता के के छावड़ा ने विरोध जताते हुए उस कर्मचारी से पूछा की इसी मार्केट के एक दो दुकानो के शेड तोड़ने के लिए क्या डी सी के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं तब उसका जवाब जनता के बीच में था हा।

अब आप बताए की क्या एक एमसीडी कर्मचारी किसी को आकर बिना नोटिस जारी किए या बिना पूर्व सूचना के ऐसी धमकियां देने के लिए कानून और नियम में सक्षमता प्राप्त है और अगर नहीं तो किस की ताकत पर वह क्षेत्र में ऐसा बोलकर गया, जनता जवाब चाहती है।

शहीद भगतसिंह कालोनी में साफ़ सफाई का बुरा हाल है बरसाती नालियां जाम है, कुड़े के ढेर लगे हुए है गलियां टुटी हुई है इस पर निगम पार्षद और डीसी का ध्यान दौरे के दौरान नहीं गया।

जनसेवक के के छावड़ा ने कहा कालोनी में जहां भी कानून की दृष्टी में अवैध कब्जा है उसे जरूर तोड़ा जाये लेकिन कालोनी में साफ सफाई और नालियों की साफ सफाई जो निगम पार्षद, डीसी और एमसीडी का मुख्य काम है वह तो करे और करवाए।

घर के प्रेत या पितर रुष्ट होने के लक्षण और उपाय

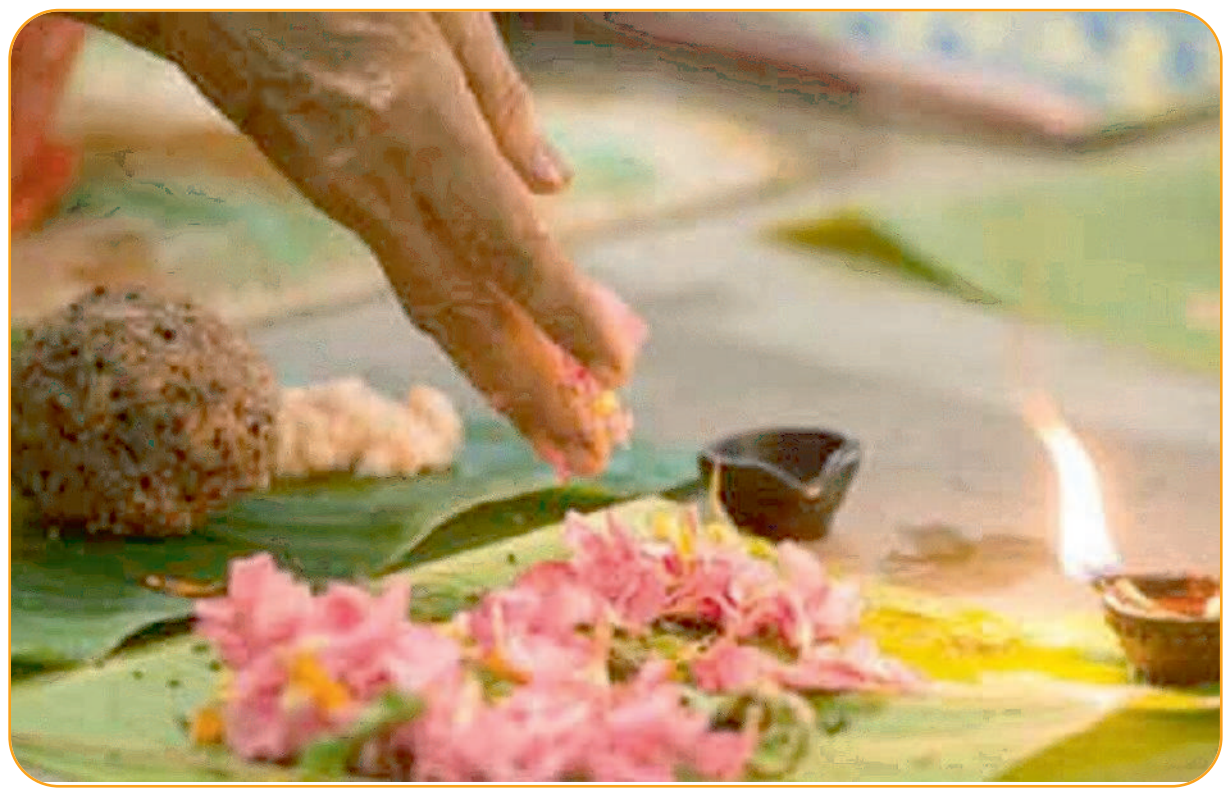

बहुत जिज्ञासा होती है आखिर ये पितृदोष है क्या ? पितृ -दोष शांति के सरल उपाय पितृ या पितृ गण कौन हैं ?आपकी जिज्ञासा को शांत करती विस्तृत प्रस्तुति।

पितृ गण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है ,क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है मनुष्य लोक से ऊपर पितृ लोक है,पितृ लोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इस से भी ऊपर स्वर्ग लोक है।

आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृ लोक में जाती है ,वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं की इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढती है।

वहाँ से आगे ,यदि और अधिक पुण्य हैं, तो आत्मा सूर्य लोक को भेज कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है,लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है ,जो परमात्मा में समाहित होती है जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता मनुष्य लोक एवं पितृ लोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा वश ,मोह वश अपने कुल में जन्म लेती हैं।

पितृ दोष क्या होता है ? हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं ,और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं,ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं,जिसे ₹पितृ- दोष₹ कहा जाता है।

पितृ दोष एक अदृश्य बाधा है .ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं ,आपके आचरण से,किसी परिजन द्वारा की गयी गलती से ,श्राद्ध आदि कर्म ना करने से ,अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है।

इसके अलावा मानसिक अवसाद,व्यापार में नुक्सान परिश्रम के अनुसार फल न मिलना विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरिअर में समस्याएं या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते, कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए उसका शुभ फल नहीं मिल पाता।

पितृ दोष दो प्रकार से प्रभावित करता है

1.अधोगति वाले पितरों के कारण

2.उर्ध्वगति वाले पितरों के कारण

अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण,की अतृप्त इच्छाएं ,जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर,विवाहादिमें परिजनों द्वारा गलत निर्णय .परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं ,परिवार जनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं।

उर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते ,परन्तु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं।

इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिलकुल बाधित हो जाती है ,फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किये जाएँ ,कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किये जाएँ,उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृ दोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि किस गृह के कारण और किस प्रकार का पितृ दोष उत्पन्न हो रहा है ?

जन्म पत्रिका और पितृ दोष जन्म पत्रिका में लग्न ,पंचम ,अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृ दोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शनि और राहू -केतु की स्थितियों से पितृ दोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु ,शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृ दोष में महत्वपूर्ण होती है इनमें सूर्य से पिता या पितामह , चन्द्रमा से माता या मातामह ,मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकाँश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु ,शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृ दोष उत्पन्न होता है ,इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले , तो पितृ दोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृ दोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है।

विभिन्न ऋण और पितृ दोष हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने (ऋण न चुकाने पर) हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है ,ये ऋण हैं : मातृ ऋण ,पितृ ऋण ,मनुष्य ऋण ,देव ऋण और ऋषि ऋण।

मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग जिनमें मा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके तीन पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है ,अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है,तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं ,इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है।

पितृ ऋण पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा ,ताऊ ,चाचा, दादा-दादी और इसके पूर्व की तीन पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है पिता हमें आकाश की तरह छत्रछाया देता है,हमारा जिंदगी भर पालन -पोषण करता है ,और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज के के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नयी पीढ़ी कर रही है ?पितृ -भक्ति करना मनुष्य का धर्म है ,इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नयी पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है ,इसमें घर में आर्थिक अभाव,दरिद्रता ,संतानहीनता ,संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि।

देव ऋण माता-पिता प्रथम देवता हैं,जिसके कारण भगवान गणेश महान बने ।इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी ,दुर्गा माँ ,भगवान विष्णु आदि आते हैं ,जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है ,हमारे पूर्वज भी भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे , लेकिन नयी पीढ़ी ने बिलकुल छोड़ दिया है इसी कारण भगवान /कुलदेवी /कुलदेवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट /श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं।

ऋषि ऋण जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए ,वंश वृद्धि की ,उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नयी पीढ़ी कतराती है ,उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं,इसलिए उनका श्राप पीडी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है।

मनुष्य ऋण माता -पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया ,दुलार दिया ,हमारा ख्याल रखा ,समय समय पर मदद की गाय आदि पशुओं का दूध पिया जिन अनेक मनुष्यों ,पशुओं ,पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की ,उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। लेकिन लोग आजकल गरीब ,बेबस ,लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है,वंश हीनता ,संतानों का गलत संगति में पड़ जाना,परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना ,परिवार कि सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृ दोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है रामायण में श्रवण कुमार के माता -पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा,ये जग -ज़ाहिर है इसलिए परिवार कि सर्वोन्नती के पितृ दोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है।

पितृों के रूष्ट होने के लक्षण पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार एकत्रित किए है वे क्रमशः इस प्रकार हो सकते है।

खाने में से बाल निकलना अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है, यह बाल कहां से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहां तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहां पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उडाते है।

बदबू या दुर्गंध कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहां से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते है कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे संभव है

पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफी सालों तक चला पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की परंतु पुत्र मिलने नहीं आया, पिता का स्वर्गवास हो गया हुआ। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है।

शुभ कार्य में अड़चन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है।

घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता।

मकान या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में दिक्कत आना आपने देखा होगा कि कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्ही कारणों से बिक नहीं पा रहा यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ऐसी कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो।

संतान ना होना मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है हालांकि आपके पूर्वजों का इस से संबंध होना लाजमी नहीं है परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होंगी इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या पता हमारे इस लेख से ऐसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिले इसलिए निवारण भी स्पष्ट कर रहा हूं।

पितृ-दोष कि शांति के उपाय

1. सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान ,सर्प पूजा ,ब्राह्मण को गौ -दान ,कन्या -दान,कुआं ,बावड़ी ,तालाब आदि बनवाना ,मंदिर प्रांगण में पीपल ,बड़(बरगद) आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मन्त्रों का जाप आदि करना ,प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद्भागवत का पाठ करना चाहिए।

2. वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र ,स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो ,शांत हो जाती है अगर नित्य पठन संभव ना हो , तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए।

वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृ दोष है उस पितृ दोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है।

3. भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठ कर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृ- दोष संकट बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है ।मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं :

मंत्र : ₹ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात।

4. अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल बूरा ,घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृ दोष शांत होता है।

5. अपने माता -पिता ,बुजुर्गों का सम्मान,सभी स्त्री कुल का आदर /सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं।

6. पितृ दोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए ₹हरिवंश पुराण ₹ का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें।

7. प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुन्दर काण्ड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है।

8. सूर्य पिता है अतः ताम्बे के लोटे में जल भर कर ,उसमें लाल फूल ,लाल चन्दन का चूरा ,रोली आदि डाल कर सूर्य देव को अर्घ्य देकर ११ बार ₹ॐ घृणि सूर्याय नमः ₹ मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है।

9. अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध ,चीनी ,सफ़ेद कपडा ,दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए।

10. पितृ पक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें अगर १०८ परिक्रमा लगाई जाएँ ,तो पितृ दोष अवश्य दूर होगा।

विशिष्ट उपाय :

1. किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज़ उसमें जल डालें ,उसकी देख -भाल करें ,जैसे-जैसे वृक्ष फलता -फूलता जाएगा,पितृ -दोष दूर होता जाएगा,क्योकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी -देवता ,इतर -योनियाँ ,पितर आदि निवास करते हैं।

2. यदि आपने किसी का हक छीना है,या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है,तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें।

3. पितृ दोष से पीड़ति व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात एक माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। एक माह बीतने पर जो अमावस्या आये उस दिन एक प्रयोग और करें इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोडा सा गौ -मूत्र प्राप्त करें उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे ५ अगरबत्ती ,एक नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें,और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें ऐसा करने पर पितृ दोष शांत हो जायेगा।

4. घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो ,उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें,क्योंके ये पितृ स्थान माना जाता है इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृ दोष शांत होता है।

5. अगर पितृ दोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो,संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने-अनजाने में किये गए अपराध / उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें ,फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का सवा लाख विधि से जाप कराएं जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प ले की इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं ,क्योंके उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है।

6. पितृ दोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है,वोह ये कि- किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना ।(लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए ,केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं)।इस से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं ,क्योंकि इसके परिणाम स्वरुप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज़ मिलता है ,जिस से वह ऊर्ध्व लोकों की ओरगति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं.।

7. अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृ दोष उत्पन्न करती है तो तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सदगति के लिए ₹गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र ₹ का पाठ करना चाहिए।

8. पितृ दोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय : इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण (N -W)में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृ पक्ष में नित्य लगाना चाहिए+दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है ,दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है।

इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धूनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं ,शाम को आंध्र होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में साड़ी सामग्री रख कर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या बड़ किजद में रख कर आ जाएँ,पीछे मुड़कर न देखें।नित्य प्रति घर में देसी कपूर जाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं,जो सरल भी हैं और प्रभावी भी,और हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृ दोषों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है।

पितृदोष निवारण के लिए करें विशेष उपाय (नारायणबलि-नागबलि) :-

अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है।

यह दोषी पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है, जब तक कि इसका विधि-विधानपूर्वक निवारण न किया जाए। आने वाली पीढ़ीयों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय हैं जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायणबलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नागबलि भी होती है।

क्या है नारायणबलि और नागबलि:- नारायणबलि और नागबलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायणबलि और नागबलि दो अलग-अलग विधियां हैं। नारायणबलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नागबलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न करना पड़ता है।

इन कारणों से की जाती है नारायणबलि पूजा :- जिस परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ हो उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है, जब तक कि पितरों के निमित्त नारायणबलि विधान न किया जाए ।प्रेतयोनी से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायणबलि की जाती है ।परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हुई हो। आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है।

क्यों की जाती है यह पूजा. ? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायणबलि-नागबलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता-पिता जीवित हैं वे भी यह विधान कर सकते हैं ।संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है ।यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भ धारण से पांचवें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म एक साल तक नहीं किए जा सकते हैं। माता-पिता की मृत्यु होने पर भी एक साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना गया है।

कब नहीं की जा सकती है नारायणबलि-नागबलि :- नारायणबलि गुरु, शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णण सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित है। नारायणबलि कर्म के लिए धनिष्ठा पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है ।धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, शततारका, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद एवं रेवती, इन साढ़े चार नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तराभाद्रपद ये छह नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय यह कर्म किया जा सकता है।

पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय :- नारायणबलि- नागबलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवाकर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे में भी संपन्न कराया जाता है। संपूर्ण पूजा तीन दिनों की होती हैं।

गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने का विधेयक भ्रष्टाचार पर नहीं, विपक्ष पर हमला है

'जनहित, कल्याण और सुशासन₹ के नाम पर पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 वास्तव में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने और भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा एक कठोर कानून है। बदले की राजनीति के दौर में, जहाँ विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जाता है, इस विधेयक के प्रावधानों को गुप्त उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस विधेयक में 'संवैधानिक नैतिकता₹ का उल्लेख करना इसकी मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि यह इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि अयोग्यता और दंड केवल आरोपों या गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि अदालतों द्वारा दोष सिद्धि से जुड़ा होना चाहिए। दोष सिद्धि के इस सिद्धांत का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 8 में स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। आज के घातक राजनीतिक माहौल में, जहां व्यक्तियों पर आसानी से आरोप लगाए जा सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, इस कानून का निश्चित रूप से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक मानदंडों को खत्म करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रियाओं और पूर्वापेक्षाओं का विवरण दिया गया है और स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति ₹प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति₹ और ₹मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल₹ को प्रदान की गई है। प्रस्तावित संशोधन इस संवैधानिक मंशा का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अप्रमाणित आपराधिक आरोपों पर स्वतः निष्कासन इन गारंटियों का उल्लंघन करता है। यह सबूत का भार और निर्दोष होने की धारणा को ही उलट देता है। इस विधेयक में समीक्षा का कोई खंड भी नहीं है। एक बार हटाए जाने के बाद, बरी होने या 30 दिन की अवधि के बाद जमानत मिलने पर भी मंत्री स्वतः अपने पद पर वापस नहीं आ सकते। अगर गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो मुआवजे का भी कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, यह निवारक निरोध और यूएपीए जैसे कानूनों के दुरुपयोग को ही बढ़ावा देगा।

जहाँ तक केंद्रीय एजेंसियों की बात है, आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मौजूदा सत्ताधारी व्यवस्था का पसंदीदा पिट्ठू बन गया है। बहरहाल, ईडी का रिकॉर्ड बेहद खराब है और पिछले पाँच सालों में केवल 38 मामलों में ही दोषसिद्धि साबित हुई है। इसकी बेहद कम दोष सिद्धि दर इस तथ्य को भी उजागर करती है कि ज़्यादातर मामले कभी सुनवाई के चरण तक भी नहीं पहुँच पाते। 2014 से 2022 के बीच ईडी द्वारा जिन प्रमुख राजनेताओं की जांच की गई, उनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी नेता थे। पीएमएलए के तहत ज़मानत मिलना दुर्लभ है, खासकर उन दो जुड़वां शर्तों के कारण -- सरकारी वकील को ज़मानत अर्जी का विरोध करने का मौका मिलना और अदालत का यह संतुष्ट होना कि व्यक्ति दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है -- जो धारा 45 के तहत पूरी होनी चाहिए। अगर यह विधेयक कानून बन गया, तो ऐसी ज्यादतियाँ और भी बढ़ जाएँगी!

इस विधेयक पर चार गंभीर आपत्तियाँ उठाई जानी चाहिएं। पहली, यह निर्दोष होने की धारणा का उल्लंघन करता है। यह मंत्रियों को केवल गिरफ्तारी पर ही दंडित करता है, दोषसिद्धि पर नहीं। इस प्रकार, ₹दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने₹ की संवैधानिक गारंटी को नष्ट करता है और प्रतिशोध के लिए कार्यपालिका के हाथ का एक हथियार बन जाता है। दूसरी, यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। स्वचालित निष्कासन संसदीय और न्यायिक निगरानी को दरकिनार कर देता है, कार्यपालिका के हाथ में अनियंत्रित शक्ति को केंद्रित करता है और बुनियादी संवैधानिक जाँच और संतुलन का उल्लंघन करता है। तीसरी, मंत्री पद से निष्कासन के लिए उचित प्रक्रिया से इंकार किया जा रहा है। मुकदमे, आरोप-निर्धारण या न्यायिक निष्कर्ष के बिना कोई भी निष्कासन उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है, जैसा कि रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में स्थापित किया गया था। चौथी, यह राजनीतिक दुरुपयोग के लिए एक मंच तैयार करता है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाली केंद्रीय एजेंसियों की वर्तमान सुस्थापित प्रवृत्ति के तहत, यह विधेयक स्वच्छ शासन को बढ़ावा देने के बजाय बदले की भावना को संवैधानिक रूप देने का जोखिम उठाता है।

यह विधेयक भारत के संवैधानिक ढाँचे पर एक अभूतपूर्व हमला है। यह विपक्ष और हमारे लोकतंत्र को दबाने के मोदी सरकार के तानाशाही प्रयास का प्रकटीकरण है, जो उसके नव-फासीवादी चरित्र को दर्शाता है। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को मुकदमे से पहले हिरासत में लिए जाने और केवल गिरफ्तारी पर स्वतः पदच्युत करके, यह विधेयक निर्दोष होने और उचित प्रक्रिया की अवधारणा को नष्ट कर देता है, जो कानून और न्याय की एक सार्थक प्रणाली के आधार हैं। यह केंद्रीय एजेंसियों को मनमानी शक्ति प्रदान करता है, जिससे विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध के द्वार खुल जाते हैं। अभियोजन को हथियार बनाने का चलन पहले से ही चल रहा है और इसे संवैधानिक रूप से पवित्र नहीं बनाया जा सकता।

-(आलेख : एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते)

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

'स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार से है। प्रत्येक व्यक्ति का यह मूलभूत अधिकार है कि उसे किसी भी प्रकार की यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का शिकार न होना पड़े।

यातना केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं देती, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर इंसान को तोड़ देती है। अपमानजनक व्यवहार समाज की आत्मा पर गहरी चोट करता है और मानवाधिकारों की नींव को कमजोर करता है। किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी मानवता और न्यायप्रियता में होती है, न कि भय और हिंसा में।

हम सभी का कर्तव्य है कि हम ऐसी किसी भी व्यवस्था, सोच या कार्य का विरोध करें जो इंसान की गरिमा छीनने का प्रयास करे। चाहे वह कानून लागू करने वाली एजेंसी हो, संस्थान हों या व्यक्तिगत स्तर पर किया गया उत्पीड़न—हर रूप में इसका प्रतिरोध होना चाहिए।

याद रखें, मानवता तभी सुरक्षित है जब प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा मिले।

क्या आप जानते हैं

क़ानून के समक्ष समानता का अधिकार

१. हर व्यक्ति समान है और क़ानून के सामने किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, जन्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

२. यह अधिकार यूडीएचआर (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स) आर्टिकल 7 और भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14 में सुनिश्चित किया गया है।

2. अमानवीय या अपमानजनक दंड से मुक्ति

१. किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता।

२. यह अधिकार यूडीएचआर (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स) आर्टिकल 5 और भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के अंतर्गत

सुरक्षित है।

आइए, मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ 'स्वतंत्रता' का मतलब हो—बिना भय, बिना यातना और बिना अपमान के जीना। यही सच्चे लोकतंत्र और सभ्यता की पहचान है।'

'उफ्तत्सा' राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 'ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी' (UFTSA) ने की सम्पूर्ण भारत में ट्रक और ट्रेलर वाहनों पर परिवहन विभाग (RTO) तथा पुलिस द्वारा लगाए जा रहे भारी चालान और जुर्माने की विभिन्न घटनाओं की कड़ी निंदा

परिवहन विशेष न्यूज

'उफ्तत्सा' राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 'ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी' (UFTSA), जो देशभर के सारथी, ट्रक और ट्रेलर चालकों व परिवहन व्यवसायियों के हितों की रक्षा करने वाला प्रमुख संगठन है, आज सम्पूर्ण भारत में ट्रक और ट्रेलर वाहनों पर परिवहन विभाग (RTO) तथा पुलिस द्वारा लगाए जा रहे भारी चालान और जुर्माने की विभिन्न घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। यह मोर्चा इन कार्रवाइयों को चालकों के लिए उत्पीड़न का माध्यम मानता है, जो न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाता है बल्कि सड़क सुरक्षा के नाम पर अनुचित दबाव डालता है। मोर्चा ने इन घटनाओं को समाहित कर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता, उचित दंड की सीमा और गलत चालानों की जांच शामिल है।

पिछले वर्षों में, विशेष रूप से 2024 और 2025 में, देश के विभिन्न राज्यों में ट्रक और ट्रेलर चालकों पर ओवरलोडिंग, डाला हाईट, प्रदूषण प्रमाणपत्र की कमी, स्पीडिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन के नाम पर अरबों रुपये के ई चालान व सामान्य विसिआर काटे गए हैं। इनमें से कई मामलों में चालक और मालिकों को बिना उचित जांच के दंडित किया गया, जिससे परिवहन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मोर्चा के अनुसार, ये कार्रवाइयां न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक हैं बल्कि कभी-कभी हिंसक घटनाओं को भी जन्म देती हैं। नीचे कुछ प्रमुख घटनाओं का ब्योरा दिया गया है, जो सम्पूर्ण भारत से एकत्रित हैं जैसे दिल्ली में ट्रक चालकों पर रिकॉर्ड चालानः 2024 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक चालकों पर 55,048 चालान जारी किए, जो पिछले वर्ष के 28,422 से दोगुना था। इनमें अधिकांश ओवरलोडिंग और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित थे, जिससे चालकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। इसी तरह, एक राजस्थान के ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए 1,41,700 रुपये का चालान भुगतान करना पड़ा। एक अन्य मामले में, एक ट्रक चालक को ओवरलोडिंग के लिए 56,000 रुपये और अन्य उल्लंघनों के लिए 70,000 रुपये का दंड लगाया गया, जबकि मालिक पर 74,500 रुपये का जुर्माना था, कुल 2,00,500 रुपये।

ओडिशा में करों और परमिट की कमी पर भारी जुर्माना हुआ- संबलपुर में एक नागालैंड के ट्रक मालिक को जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक कर न चुकाने, परमिट न होने और अन्य अपराधों के लिए 6,53,100 रुपये का चालान जारी किया गया।यह घटना दर्शाती है कि पुराने नियमों के आधार पर भी चालक दंडित हो रहे हैं।

हरियाणा में ओवरलोडिंग और सतर्कता की घटनाएं में एक ट्रक ऑपरेटर पर 18 टन से अधिक सामान लादने के लिए 2,00,000 रुपये से ऊपर का जुर्माना लगाया गया।गुरुग्राम में एक ट्रक चालक को विभिन्न उल्लंघनों के लिए 59,000 रुपये का चालान जारी किया गया। एक अन्य घटना में, गौ रक्षकों और पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक को स्पाइक स्ट्रिप्स से रोका, संदेह था कि गायें ले जा रहा था, लेकिन इसमें कपड़े थे, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और चालक को बड़ा नुकसान हुआ।

राजस्थान में हिंसक घटनाएं के रूप में कोटा में एक RTO इंस्पेक्टर को चालान काटने पर ट्रेलर चालक ने कुचलकर मार डाला सुनिश्चित है जो की बिल्कुल ही नींदणीय है किंतु इसमें चालक परेशान होकर इस तरह के कदम उठाते हैं जोधपुर में चालान बनाने के दौरान परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ, वाहन के शीशे फोड़े गए। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कभी-कभी गलत चालान प्रक्रिया हिंसा को भी बढ़ावा देती है।

बिहार में ई-चालान की समस्या के अन्तर्गत टोल प्लाजाओं पर 7 अगस्त 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक 1.5 लाख वाहनों पर 80 करोड़ रुपये के ई-चालान काटे गए, जिससे चालकों वह मालिकों में अच्छी खासी नाराजगी है।एक मामले में राजस्थान पुलिस ने बिहार पंजीकृत गाड़ी का गलत चालान काटा, जहां स्पीड कम होने पर ओवरस्पीडिंग का जुर्माना लगाया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर चालान काटा गया यह एक सुखद एहसास था कि नियमों को पूरी तरजीह देनी चाहिए

असम में ओवरलोडिंग अभियानः 30 मई से 1 जुलाई 2021 तक 2,217 मामलो में 15.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, मुख्यतः ओवरलोडिंग के लिए।हालांकि यह पुराना डेटा है, लेकिन समस्या लगातार जारी है।

महाराष्ट्र में हड़ताल और बकाया चालान में ई-चालान प्रणाली के विरोध में लाखों ट्रक और वाहन हड़ताल पर गए। एक वाहन पर 52 हाईवे चालान बकाया थे, कुल 11.16 लाख रुपये, अधिकांश ओवरस्पीडिंग और लाइसेंस न होने के।

देशव्यापी आंकड़े के अनुसार 2024 में पूरे भारत में 8 करोड़ चालान जारी किए गए, कुल 12,000 करोड़ रुपये के जुर्माने, जिसमें ट्रक और ट्रेलर बड़े हिस्सेदार हैं। नोएडा में 27.9 लाख चालानों में से केवल 2.8% रिकवरी हुई। उत्तर प्रदेश में 3 लाख गाड़ियां बकाया चालानों के कारण कबाड़ घोषित होने वाली हैं जिसकी प्रक्रिया भी चालू है।

वही सबसे बड़ी समस्या है कि विभिन्न राज्यों में चालान व जुर्माने को लेकर विषम विसंगतियां पाई गई हैं जो चालान उदाहरणतः झारखंड में 2000 का माना जाता है (वैसे चालान प्रताड़ना में झारखण्ड अग्रिम पंक्ति में है) तो वही चालान हरियाणा में 35000 भी हो जाता है कुछ मामले में महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत वहीं उल्लंघन में 40000 के चालान होते हैं,एंव वहीं उल्लंघन चालान दिल्ली में 60000 के 1 कहीं आवर हाइट का फरमान 2000/- तो हरियाणा विश्व रिकार्ड बना रहा है 1 अलग ही क़ानून और अलग ही बही खाता है, कहीं 5% ग्रेस वेट को लेकर छूट है तो वहीं झारखंड जैसे राज्य में चालकों के अनुसार परिवहन अधिकारी यहां तक भी कह देते हैं कि मुख्यमंत्री से भी लिखावा लाओ तो भी नहीं मानेंगे, क़ानून बतियाओगे तो गाड़ी सड़वा देंगे जब्ती से 1 कहीं चालानो के भुगतान कैस वसूली के रूप में की जाती है तो कहीं बिना सुने ही अदालत फॉरवर्ड कर दिया जाता है 1 जीएसटी फार्म में परिवहन की समय सीमा खत्म हो या गलत एंट्री हो गई हो तो तीन चार लाख का जुर्माना भी आम बात है, गाड़ी मालिकों व चालकों को सड़क पर चलते भेड़ बकरी से भी निचे का दर्जा दिया गया है जो जब चाहे हलाल करने के लिए चालान रूपी हथियार उठा लेता है 1 ₹एक देश - एक विधान - एक संविधान₹ की नीति पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे लिए तो टैक्स की प्रणालीयों जीएसटी को भी समान नहीं रखा गया है यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है 1 हमें तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है कि जब हम आजाद देश के आजाद नागरिक बनकर समान धारा में शामिल होकर समान नागरिक संहिता के साथ खुले माहौल में बिना डर के बिना आतंकित हुए पूरे देश के लिए समर्पित होकर परिवहन व्यवसाय का काम करते हुए परिवहन उद्योग को एक नए मंजिल तक पहुंचा सकें 1 चेहरे पर एक अदद मुस्कान के लिए दशकों से हमारी लड़ाई जारी है, न जाने कब पूरा होगा लेकिन अच्छे दिनों के विषय में सोचना कौन सा गुनहगारी है 1 'उफ्तत्सा' राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 'ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कहा, ₹ये चालान न केवल अनुचित हैं बल्कि परिवहन उद्योग को बर्बाद कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार चालान प्रक्रिया की समीक्षा करे, ई चालान बंद हो, गलत चालानों पर रोक लगाए और चालकों व गाड़ी मालिकों को राहत दे। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो अनिश्चित कालीन देशव्यापी आंदोलन में देर नहीं 1 आज ई-चालान सर दर्द के कारण बना हुआ है इसके वजह से न जाने कितने गाड़ी मालिक कितने चालक आत्महत्या के कगार पर हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, गाड़ी लखनऊ में खड़ी होती है चालान बड़बिल में होता है 1 जिस ट्रक/ट्रेलर को इंजन की वजह से तीव्र गति से नहीं चलाया जा सकता वही गाड़ी का ओवर स्पीड चलन भी होता है 1 जो कई महीनो से गेराज में खड़ी होकर मरम्मत का काम करवा रही होती है उनका ही नो पार्किंग का चालान किसी और राज्य में कट जाता है 1 ई चालान को सुगमता के लिए बनाया गया था लेकिन यह एक भ्रष्टाचार का कारण बनती जा रही है और इसे शीघ्रता शीघ्र बंद करना चाहिए 1

● भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्व. अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर आज अरुण जेटली पार्क में आयोजित समारोह में श्रद्धासुमन अर्पित किए ।

● स्व. अरुण जी का मेरे प्रति विशेष स्नेह रहा। उनसे निसंकोच अपने मन की बातें साझा कर पाना और उनका स्नेहिल मार्गदर्शन मिलना, मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है– राजेश भाटिया ।

हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को सभी आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं समय पर मिलें-वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता

दिल्ली में रामलीला एवं दुर्गा पूजा की तैयारियां प्रारम्भ हो चुकी हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह के साथ लाल किला परेड़ मैदान में आयोजित होने वाली नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के भूमी पूजन में सम्मिलित हुए और तत्पश्चात सचदेवा ने पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी के साथ प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बंगाल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा समितियों की बैठक को सम्बोधित किया।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि रामलीला मंचन हो या दुर्गा पूजा दोनों सत्य की असत्य पर विजय के प्रतिक हैं और भारत की धार्मिक एवं सामाजिक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि कमेटी एवं दुर्गा पूजा समितियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर नई पीढ़ी के बीच संस्कार सृजन का काम कर रही हैं।

वीरेन्द्र सचदेवा एवं लॉकेट चैटर्जी ने बंगाल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठक में प्रभारी तपस रॉय और संयोजक किशोर तरफदार एवं सह संयोजक अरूण मुखर्जी के साथ दिल्ली के विभिन्न कोनों से आये दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। दिल्ली भाजपा के प्रकोष्ठ संयोजक अशोक ठाकुर भी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को सभी आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं समय पर मिलें।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की पुण्य तिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केन्द्रीय नेताओं, उपस्थिती में श्रद्धांजली अर्पित की

मुख्य संवाददाता सुषमा रानी

नई दिल्ली 24 अगस्त : पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरूण जेटली की छठी पुण्य तिथि पर आज नई दिल्ली में अरूण जेटली पार्क प्रांगण में आयोजित एक श्रद्धांजली सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा परिवार की ओर से उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए।

नड्डा के साथ केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण एवं धर्मेन्द्र प्रधान, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत एवं बाँसुरी स्वराज, विधायक सतीश उपाध्याय, अनिल शर्मा, नीरज बसोया एवं शिखा रॉय, कार्यालय मंत्री बृजेश राय आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किये।

विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में जेल भेजकर उनकी सरकारें गिराने की लिए बिल ला रही मोदी सरकार - संजय सिंह

मुख्य संवाददाता

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को झूठे केस में जेल भेजने, खरीद फरोख्त कर सरकारों को गिराने और उनकी पार्टी खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। मोदी और भ्रष्टाचारियों का प्यार लैला-मजनूँ हीर-राँझा और रोमियो- जूलिएट की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है। केंद्र सरकार द्वारा बिल को लेकर बनाई जा रही केंद्र जेपीसी में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर रविवार को कहा कि केंद्र सरकार एक गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक बिल ला रही है। इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, तोड़ना, खरीद-फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डालना और उनका इस्तीफा लेना है। यह बिल लोकतंत्र को खत्म करने के इरादे से लाया जा रहा है। इसलिए "आप" और अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम सरकार द्वारा बनाई जा रही जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में शामिल नहीं होंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह साफ समझ लीजिए कि यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भाजपा का भ्रष्टाचारियों से वैसा ही प्रेम है, जैसा रांझा का हीर से, लैला का मजनू से या रोमियो का जूलियट से था। भाजपा और पीएम मोदी को भ्रष्टाचारियों से प्यार है। अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, जी. जनार्दन रेड्डी, बी.एस. येदियुरप्पा, शारदा-नारदा घोटाले के मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा ये सारे भ्रष्टाचारी आज किस पार्टी में हैं?

संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम सीना ठोककर देश की हजारों-लाखों करोड़ की संपत्तियां अपने दोस्त अडानी को सौंप रहे हैं। यह कैसा भ्रष्टाचार विरोधी रवैया है? उनकी बात पर कौन यकीन करेगा कि यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ है? उनकी पार्टी तो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है। तो यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टियों को खत्म करने, विधायकों की खरीद-फरोख्त करने, सरकारें गिराने और विपक्ष को जेल में डालने के लिए लाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम इस जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे।

उन्होंने एक्स पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के सरदार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिल कैसे ला सकते हैं? नेताओं को फ़र्ज़ी मामले में फँसाना और जेल में डालना सरकारों को गिराना इस बिल का उदेश्य है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी शामिल न होने का फ़ैसला लिया है।

कर्नल ढिल्लो के प्रयास और सेना की सार्थक मुहिम का नाम है "ऑपरेशन माँ"

मुख्य संवाददाता

साउथ दिल्ली में सिलेक्ट सिटी माल के सिने पॉलिश मल्टीप्लेक्स में सेना के उसी अधिकारियों के साथ प्रशासनिक सेवा के आला अफसरों के साथ मीडिया पर्सन की मौजूदगी में कश्मीर की अनेक रियल लोकेशन में शूट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑपरेशन मां की विशेष स्क्रीनिंग के उपरान्त इस डॉक्यूमेंट्री के प्रेरणा स्त्रोत लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन (सेवानिवृत्त) ने यहां मौजूद मीडिया से बातचीत की।

उन्होंने कहाः "जब हमने घाटी में अपनी राह से गुमराह होकर आतंक का रास्ता चुन चुके युवकों को आतंक का रास्ता छोड़ के एक बार फिर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने का ऑपरेशन शुरू किया तो हमने सबसे पहले इन युवकों की मां को अप्रोच किया और हमारी यह मुहिम अच्छा रंग लाई उस दौरान करीब 80 से ज्यादा युवकों ने कट्टरपंथियों के बहकावे और पड़ोसी मुल्क के लालच को छोड़ शांति का रास्ता चुना,जिसका पूरा क्रेडिट हम इनकी मां को देते है।

ढिल्लो साहब से जब हमने इस डॉक्यूमेंट्री के टाइटल के बारे में पूछा इसका पूरा क्रेडिट मैं पीटीआई में इस ऑपरेशन पर एक रिपोर्ट छपी जिसके टाइटल में ऑपरेशन माँ' लिखा था यह हम सब को पसंद आया और हमने टाइटल को अपनाया ।

कर्नल ढिल्लो ने बताया इस ऑपरेशन में हमारा लक्ष्य बस इतना था कि गुमराह हो चुकी युवा पीढ़ी को किसी भी तरह से उनकी, माँ के पास वापस लाया जाए।। हम जानते है कि माँ के

प्यार की ताकत का मुकाबला कोई भी हथियार नहीं कर सकता और इस्लाम में तो मां को जन्नत का दर्जा दिया गया है , और हमारी यह फिल्म इसी भावना को बखूबी दर्शाती है।

आईएन10 के निदेशक आदित्य पिट्टी ने कहा, ₹'ऑपरेशन माँ' एकता, करुणा और आशा के मूल्यों को दर्शाता है जो हमारी आज़ादी के मूल में निहित हैं।₹ डॉक्यूबेवी के समर खान ने कहा, हमने घाटी के लोगों के सहयोग से राष्ट्र की अंतरात्मा से जुड़ी इस कहानी पर लंबी रिसर्च के बाद कड़कती सर्दी में रीयल लोकेशन पर करीब चार महीने तक शूटिंग की।उन्होंने कहा, ₹घाटी भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ का हर बेटा घर लौटने का हक़दार है।₹ऑपरेशन माँ₹ का प्रीमियर विशेष रूप से 27

गोंदिया में साईं झूलेलाल व बाबा खाटूश्याम जी का अदभुत मिलन - सामाजिक समरसता की मिसाल कायम - भक्तों का सैलाब उमड़ा

साईं झूलेलाल चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 25 अगस्त 2025- झूलेलाल मंदिर में बाबा श्यामखाटू जी भजन समिति का भव्य भजन कीर्तन संध्या
दो सामाजों की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक साईं झूलेलाल व बाबा श्याम खाटू जी के कृपा पात्र साधकों भक्तों संगतो का सराहनीय भाव भक्ति प्रेम उमड़ पड़ा-
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया की पावन धरती पर 23 अगस्त 2025 में एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने न केवल स्थानीय भक्तों को,बल्कि देशभर के लोगों को सामाजिकसमरसता और आध्यात्मिक आस्था के अद्भुत संगम का संदेश दिया। यह अवसर था साईं झूलेलाल चालीसा महोत्सव का, जो 16 जुलाई से 25 अगस्त 2025 तक चलने वाला है। इस महोत्सव की गरिमा और भव्यता 23 जुलाई 2025 को चरम पर पहुँची जब गोंदिया के प्रसिद्ध झूलेलाल मंदिर में बाबा श्याम खाटूजी भजन समिति द्वारा एक अनुपम भजन-कीर्तन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर साईं झूलेलाल और बाबा श्याम के दिव्य नामों का संगम हुआ और भक्ति रस में सराबोर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित था और देखा कि यह अद्वितीय आयोजन केवल धार्मिक भावनाओं का संचार नहीं कर रहा था, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा था। झूलेलाल और खाटू श्याम जी, दोनों ही संत-देव रूप में पूजे जाते हैं और उनकी शिक्षाओं का मूल तत्व है-सत्य, सेवा, समर्पण और समरसता। जब दो अलग-अलग परंपराओं के भक्त एक मंच पर, एक स्वर में भजन-कीर्तन गाते हैं, तब यह केवल ईश्वर की आराधना नहीं होती, बल्कि यह इंसानों के दिलों को जोड़ने का कार्य भी करती है।यही दृश्य गोंदिया में उस शाम को देखने को मिला, जब हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ बैठे और प्रेम व आस्था के गान में शामिल हुए।

साथियों बात कर हम भारत की सांस्कृतिक परंपरा की करें तो, सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता रही है। यहाँ अलग-अलग समुदाय,संप्रदाय और आस्थाएँ होने के बावजूद समाज में गहरी आत्मीयता देखने को मिलती है। झूलेलाल, जिन्हें सिंधी समाज का इष्टदेव माना जाता है, और बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें राजस्थान व उत्तर भारत के लाखों लोग श्रद्धा से पूजते हैं, दोनों ही आस्था के ऐसे केंद्र हैं जिनके भक्त केवल किसी खास क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। जब इन दोनों आस्थाओं का गोंदिया में मिलन हुआ तो यह एक ₹मिनी भारत₹ का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था।

साथियों बात अगर हम जय घोष के नारों की करें तो भजन -कीर्तन संध्या में जब भक्तगण ₹जय झूलेलाल₹ और ₹श्याम तेरी भक्ति ने बड़ा कमाल किया₹ जैसे स्वर में गूँज रहे थे,तब वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। इस ऊर्जा ने केवल मंदिर परिसर को ही नहीं, बल्कि आसपास के समाज को भी एक सकारात्मक संदेश दिया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य है मानवता का उत्थान और प्रेम का विस्तार। गोंदिया की इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज प्रेम और श्रद्धा के पथ पर चलता है तो जाति-धर्म की दीवारें स्वतः गिर जाती हैं और केवल इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है, जो रेखांकित करने वाली बात है।

साथियों बात अगर हम दोनों सामाजिक शक्तियों के कुल गुरुओं की शिक्षा की करें तो,साईं झूलेलाल और बाबा खाटू श्याम जी की शिक्षाओं में भी यही भाव छिपा हुआ है। झूलेलाल जी ने सदियों पहले सिंध की धरती पर जल और जीवन की रक्षा करते हुए, समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका नाम आते ही ₹जल ही जीवन है₹ और ₹समानता₹ की धारा स्मरण हो उठती है। वहीं, बाबा श्याम खाटू जी महाभारतकालीन बर्बरीक के रूप में करुणा और दानवीरता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका संदेश है कि सच्चा भक्त वही है जो अपना सर्वस्व लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दे। जब दोनों संत-देव रूपों के संदेश एक मंच पर मिलते हैं तो यह समाज के लिए किसी दिव्य वरदान से कम नहीं होता।

साथियों बात अगर हम इस आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता की करें तो, आज का समय भले ही तकनीक और भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन मनुष्य की आत्मा को शांति केवल भक्ति, सेवा और सामाजिक समरसता में ही मिलती है। यही कारण है कि गोंदिया का यह आयोजन हर दृष्टि से ऐतिहासिक और अनुकरणीय बन गया। यहाँ हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आए, भोजन-प्रसाद ग्रहण किया, और भक्ति संगीत में डूबकर यह साबित किया कि सच्चा आनंद केवल साझा अनुभव में ही है।आस्था और अध्यात्म के ऐसे आयोजनों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये समाज में तनाव, ईर्ष्या और विभाजन को कम करते हैं और लोगों के बीच आत्मीयता की भावना को मजबूत बनाते हैं। भजन-कीर्तन संध्या केवल धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है जो यह बताती है कि एकता और प्रेम ही जीवन की सच्ची पूँजी हैं

साथियों बात अगर हम सामाजिक समरसता को खुशियों का प्रतीक माननें की करें तो, समृद्ध तथा इतिहास गवाह है कि जब-जब समाज ने धार्मिक समरसता को अपनाया है, तब-तब उसने विकास, शांति और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए हैं। गोंदिया का यह आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने यह स्पष्ट किया कि चाहे हम किसी भी समाज या समुदाय से हों, हमारे ईश्वर अलग हो सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा और हमारी भावनाएँ एक ही हैं।

साथियों मैंनें उपरोक्त पूरे आयोजन का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि (1) झूलेलाल और खाटू श्याम जी की ऐतिहासिक- धार्मिक पृष्ठभूमि-साईं झूलेलाल जी को सिंध वे जल और जीवन के संरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ₹उदरोलाल₹ या ₹वरुणावतार₹ कहे जाते हैं। उनकी कथा सिंध नदी से जुड़ी है, जहाँ उन्होंने समाज को एकता, साहस और न्याय का संदेश दिया। दूसरी ओर, खाटू श्याम जी महाभारत के वीर बर्बरीक का ही रूप हैं, जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को अपना शीश अर्पित कर लोककल्याण की मिसाल पेश की। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताती है कि दोनों ही देव रूपों का सार है- त्याग, आस्था और समाजहित।(2) दोनों आस्थाओं की शिक्षा का तुलनात्मक विशेषण- झूलेलाल जी का उपदेश है-सभी धर्मों का सम्मान करो और समाज में समानता स्थापित करो। उनकी आराधना जल, जीवन और शांति से जुड़ी है। वहीं, खाटू श्याम जी का मूल संदेश है कि सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार छोड़कर ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पित करती है। दोनों आस्थाओं का मिलन इस तथ्य को मजबूत करता है कि चाहे रास्ते अलग हों, परंतु गंतव्य एक ही है-मानवता की सेवा और ईश्वर का स्मरण। (3) गोंदिया के आयोजन की विशेषताएं और समाज पर प्रभाव-गोंदिया में आयोजित इस भजन-कीर्तन संध्या की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें हर जाति और वर्ग के लोग शामिल हुए। मंदिर का वातावरण केवल धार्मिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक एकता का मंच बन गया। इस आयोजन से समाज में भाईचारे की भावना मजबूत हुई और लोगों ने महसूस किया कि भक्ति का असली आनंद साझा अनुभव में है। (4) सामाजिक समरसता का महत्व भारतीय संविधान और संस्कृति के संदर्भ में-भारतीय संविधान ₹समानता₹, ₹धर्मनिरपेक्षता₹ और ₹बंधुत्व₹ के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं, भारतीय संस्कृति सदियों से ₹सर्व धर्म समभाव₹ और ₹वसुधैव कुटुम्बकम्₹ की धारा बहाती आई है। जब साईं झूलेलाल और खाटू श्याम के भक्त एक मंच पर मिलते हैं, तो यह संविधान की आत्मा और भारतीय संस्कृति की परंपरा दोनों का जीवंत उदाहरण बनता है। यह आयोजन संविधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय प्रस्तुत करता है। (5) आधुनिक समाज में ऐसे आयोजन की प्रासंगिकता-आज का समय तेजी से बदल रहा है। भौतिकवाद, तनाव और सामाजिक विभाजन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे दौर में झूलेलाल और खाटू श्याम जी जैसे आस्था-आधारित आयोजनों का महत्व और बढ़ जाता है। यह न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि समाज को यह भी सिखाते हैं कि सच्ची ताकत प्रेम, सेवा और सामूहिक भक्ति में है। इन आयोजनों से लोगों के बीच संवाद, सहयोग और सहिष्णुता की भावना पनपना (6)₹वसुधैव कुटुम्बकम्₹ और ₹सर्वधर्म समभाव₹ की परंपरा-भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है-₹वसुधैव कुटुम्बकम्₹ अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी प्रकार,₹सर्व धर्म समभाव₹ की परंपरा यह सिखाती है कि सभी धर्म समान हैं और प्रत्येक आस्था का सम्मान होना चाहिए। गोंदिया का यह आयोजन इन दोनों ही आदर्शों का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ अलग-अलग परंपराओं के भक्त एक साथ आए और प्रेम व भाईचारे का वातावरण निर्मित किया। यह बताता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता ही है।

अतः अगर हम अपने पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि गोंदिया में साईं झूलेलाल व बाबा खाटू श्याम जी का अदभुत मिलन-सामाजिक समरसता की मिसाल कायम- भक्तों का सैलाब उमड़ा साईं झूलेलाल चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 25 अगस्त 2025-झूलेलाल मंदिर में बाबा श्यामखाटू जी भजन समिति का भव्य भजन कीर्तन संध्या ।दो सामाजों की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक साईं झूलेलाल व बाबा श्याम खाटू जी के कृपा पात्र साधकों भक्तों संगतो का सराहनीय भाव भक्ति प्रेम उमड़ पड़ा।

कोई भी शॉर्टकट तरीका सफलता की गारंटी नहीं दे सकता: उमेश कश्यप

सुनील चिंचोलकर

महिला सशक्तिकरण सहायता फाउंडेशन सुधा प्रवाह व कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट का आयोजन
साइबर सिक्योरिटी पर व्याख्यान के साथ प्रमाण पत्र का वितरण

अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल (अकलतरा) में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट समिति के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत पाँच दिवसीय कार्यशाला में महिलाओं को केक मेकिंग, रूप सज्जा और मेहंदी जैसी कला रूपों में प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल को विकसित करने में मदद करना था। कार्यशाला के समापन पर प्रमाण पत्र वितरण एवं साइबर सिक्योरिटी पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमेश कुमार कश्यप (सहायक पुलिस अधीक्षक जांजगीर), विशिष्ट अतिथि दीप्ति रोहित सारथी (अध्यक्ष नगर पालिका अकलतरा), पारस पटेल (नगर निरीक्षक मुलमुला), ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल के संचालक डॉ. जे.के. जैन, सुधा शर्मा (कार्यशाला प्रशिक्षक कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट बिलासपुर), रोहित सारथी (भू.पू. सैनिक), राजकुमार साहू उपस्थित रहे। सहायक पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने महिला सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सराहना की और साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ठगी लिंक के माध्यम से राहतों से पैसे निकालने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए, हमें साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी शॉर्टकट या आसान तरीका सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। नगर निरीक्षक पारस पटेल ने बताया वर्तमान समय में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने छात्र- छात्राओं को हेलमेट पहनने की सलाह दी। दीति रोहित सारथी (अध्यक्ष नगर पालिका अकलतरा) ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक आंदोलन है ना कि विचार। उनहोंने बताया अहिल्या बाई होलकर की कहानी को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। रोहित कुमार सारथी (भू.पू. सैनिक) ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का आहान किया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में प्रशिक्षित सौ से ज्यादा छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। संस्था के सचिव अंकित जैन ने आगंतुकों को प्रतीकात्मक भेंट समर्पित कर उनका सम्मान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शिखा सिंह ने आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में राजेंद्र राठौर, जयंती लहरे, राजमणि द्विवेदी, केके धैर्य, रघुनंदन मार्बल, हिमांशु साहू, शीतल केडिया, निर्मला पालीवाल, प्रीति घोरे, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी अरविंद मिरी, डॉ. प्रतिमा रानी द्विवेदी, ओमप्रकाश सीनी, संजीव चौहान, दुर्गा टण्डन, चेता सिंह चंदेल, संध्या सिंह, कमलकांत साहू, नवीन आदित्य, प्रभात कश्यप, नागेंद्र जांगड़े, राहुल राठौर, अर्जुन दास मोहले, संजना भास्कर, सोनम साहू, श्रद्धा राठौर, भूपेन्द्र, चंद्ररुषा कश्यप, अशोक पाण्डेय, सुनीता पाण्डेय, पायल दास, हितेश्वरी कश्यप, रश्मि मरकाम, कृष्णकांत चंद्राकर, समरीन मिर्जा, मनीष गंधर्व, आकाश दास, नीरज निर्मलकर, बृजनंदन पटेल, द्वाशराम कश्यप, राजेश साहू एवं छात्र छात्राओ के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे।

ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर भारत का पहला रिएक्शन -25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए डाक सेवा (पोस्टल सर्विसेज) बंद

भारत की ई-कॉमर्स कंपनियां, कई स्टार्टअप्स अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं,अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर को डाक सेवाओं या लॉजिस्टिक चैनलों से पूरा करते हैं, उन पर असर पड़ेगा

भारत का अधिकतम निर्यातक एमएसएमई क्षेत्र, यानें कपड़ा, हस्तशिल्प,ज्वेलरी,आयुर्वेदिक उत्पाद,और छोटे पैमाने के तकनीकी उपकरण जैसे क्षेत्र संकट में पढ़ने की संभावना

– एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया-विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की नीतियां हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं।विशेषकर जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है, तो उनके निर्णय त्वरित, कठोर और कभी-कभी विवादास्पद भी माने जाते हैं। ट्रंप का हालिया टैरिफ एक्शन न केवल चीन और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है, बल्कि भारत भी इसके सीधे असर से अछूता नहीं है। इस नए टैरिफ वार के परिणाम स्वरूप भारत ने 25 अगस्त से एक बड़ा कदम उठाया-डाक सेवाओं को सीमित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पार्सल व गिफ्ट आइटम्स की सप्लाई को रोकना। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं यह फैसला भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक स्थिति को प्रभावित करने वाला है।इसलिए आज हम मीडिया में हो उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर भारत का पहला रिएक्शन- 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए डाक सेवा (पोस्टल सर्विसेज) बंद।

साथियों बात अगर हम सरकार के 25 अगस्त सेअमेरिका के लिए डाक सेवा बंद करने के फैसले के प्रभाव को 10 पॉइंट में समझने की करें तो (1) अब केवल 100 डॉलर (8700 रुपए) कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स और लेटर- डॉक्यूमेंट्स ही भेजे जा सकेंगे-नई व्यवस्था के तहत भारत से विदेश भेजे जाने वाले सामान पर सख्त पाबंदी लग गई है। केवल वे ही गिफ्ट आइटम्स जिनकी कीमत 100 डॉलर यानी लगभग 8700 रुपए तक है, भेजे जा सकेंगे। इसके अलावा चिट्ठियां और लेटर डॉक्यूमेंट्स की अनुमति होगी। इसका अर्थ यह है कि बड़े पैमाने पर पार्सल, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, छोटे उद्योगों के सामान, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े पैकेज विदेश नहीं भेजे जा सकेंगे। इससे भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप कंपनियां,जो अपने उत्पाद विदेशों में बेच रही थीं, सीधे प्रभावित होंगी। (2) पत्राचार की अनुमति लेकिन व्यापारिक गतिविधियों पर रोक-भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत संचार, यानी लेटर और दस्तावेज भेजने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर संवाद जारी रहना आवश्यक है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से यह एक बड़ा झटका है। जो लोग विदेशों में अपने परिजनों या ग्राहकों को गिफ्ट आइटम्स भेजते थे, वे अब सीमित रह जाएंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत ने व्यापारिक दबाव का सामना करने के लिए अपनी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से पुनर्गठित किया है।(3) पहले से बुक किए गए सामान पर पेमेंट वापसी-सरकार और डाक विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जो ग्राहक पहले ही सामान बुक कर चुके हैं और जिनका पार्सल अब नहीं भेजा जा सकता, उन्हें पूरा भुगतान वापस किया जाएगा। यह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में सही कदम है। लेकिन यह व्यवस्था केवल अस्थायी राहत है, क्योंकि निर्यातक और ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले से हुए निवेश और तैयार माल पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। (4) आम जनता पर असर-डाक सेवाओं की यह रोक आम जनता पर गहरा असर डालेगी। विदेशों में बसे परिजनों को गिफ्ट भेजने वाले परिवार, छात्र और कामकाजी लोग सीधे प्रभावित होंगे। छोटे व्यवसाय और हस्तशिल्प उद्योग, जो डाक सेवाओं के माध्यम से अपना सामान विदेश भेजते थे, अब बाजार खो देंगे। भारतीय त्योहारों के सीजन में यह फैसला विशेष रूप से दर्दनाक साबित हो सकता है। साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के वे लोग, जिनके लिए डाक सेवा ही अंतरराष्ट्रीय संचार और व्यापार का मुख्य माध्यम थी, अब ठहराव का सामना करेंगे।(5) निर्यात में 40 से 50 पेर्सेंट की कमी का अनुमान-विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। अनुमान है कि 40 से 50% तक का नुकसान हो सकता है।एमएसएमई क्षेत्र, जो भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, सबसे अधिक प्रभावित होगा। कपड़ा, हस्तशिल्प, ज्वेलरी, आयुर्वेदिक उत्पाद, और छोटे पैमाने के तकनीकी उपकरण जैसे क्षेत्र संकट में पड़ जाएंगे। यह कमी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता संतुलन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी।(6)भारत में जीएसटी

सुधार और नई स्लैब व्यवस्था-इन सबके बीच भारत सरकार ने घरेलू मोर्चे पर जीएसटी सुधार लागू करने का निर्णय लिया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5 पेर्सेंट से 18 पेर्सेंट की जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, यह कदम घरेलू व्यापारियों के लिए राहतकारी हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगी पाबंदियों के कारण इसका लाभ सीमित रह जाएगा। यह सुधार भारत की ₹आत्मनिर्भर भारत₹ नीति के अनुरूप है, जो घरेलू खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में है।(7) 50पेर्सेंट टैरिफ लागू होने का वैश्विक असर-25 अगस्त से लागू होने वाले 50 पेर्सेंट टैरिफ का असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाँ पर पड़ेगा।अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाएगी। वहीं चीन और रूस भी इस टैरिफ का सामना कर रहे हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला असंतुलित हो सकती है। यूरोप और मध्य एशिया के बाजार भारत के लिए नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक और कूटनीतिक निवेश की आवश्यकता होगी।(8) अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव-भारत का यह कदम केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।अमेरिका को स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने में सक्षम है। हालांकि,यह भारत- अमेरिका संबंधों में तनाव भी पैदा कर सकता है। वहीं चीन और रूस जैसे देशों के लिए भारत एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में और मजबूत हो सकता है। इस पूरी स्थिति से वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के देशों को भी सबक मिलेगा कि वे अमेरिका-प्रेरित नीतियों के दबाव में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कैसे करें।(9) ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदम बहुआयामी हैं। डाक सेवाओं पर रोक, निर्यात में कमी का अनुमान, जीएसटी सुधार और वैश्विक व्यापार में नए समीकरण,ये सभी घटनाएं 21वीं सदी के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती हैं। आने वाले समय में भारत को अपनी कूटनीतिक कुशलता और आर्थिक रणनीति दोनों को मजबूत करना होगा। निर्यातकों और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को नए रास्ते तलाशने होंगे। वहीं, वैश्विक स्तर पर भारत के सामने अवसर भी हैं—यूरोप, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ नए व्यापार समझौते करके भारत इस संकट को अवसर में बदल सकता है।

साथियों बातें अगर हम इ-कॉमर्स कंपनियों पर असर पड़ने की करें तो भारत की ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट,मीशो एक्सपोर्ट, अमेज़ॉन इंडिया (ग्लोबल सेलर्स प्रोग्राम) और कई स्टार्टअप्स अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। इन कंपनियों का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर को डाक सेवाओं या लॉजिस्टिक चैनलों से पूरा करता है। डाक सेवाओं के रुकने और 100 डॉलर की सीमा लागू होने से इन कंपनियों का वैश्विक कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। विशेष रूप से हस्तशिल्प, कपड़ा, ज्वेलरी, घरेलू सजावट और आयुर्वेदिक उत्पाद बेचने वाले छोटे विक्रेता नुकसान में रहेंगे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां निजी लॉजिस्टिक और कुरियर नेटवर्क का उपयोग करके कुछ हद तक इस नुकसान को झेल सकती हैं, लेकिन छोटे और मध्यम विक्रेताओं (एमएसएमई) के लिए यह एक आर्थिक झटका होगा। कई छोटे निर्यातक, जिन्होंने ₹मेक इन इंडिया₹ और ₹डिजिटल इंडिया₹ के

तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा किया था, उनके कारोबार में गिरावट आ सकती है। यह स्थिति भारतीय सरकार के लिए चुनौती है कि वह ई-कॉमर्स सेक्टर को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए।

साथिया बातें अगर हम भारतीय डायस्पोरा पर असर पढ़ने की करें तो,भारत का प्रवासी समुदाय यानी डायस्पोरा, जो दुनिया के लगभग हर देश में फैला हुआ है, इस निर्णय से गहराई से प्रभावित होगा। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय अक्सर भारत से सामान मंगवाते हैं-त्योहारों के अवसर पर मिठाइयां, कपड़े, पूजा सामग्री और पारंपरिक गिफ्ट्स। डाक सेवाओं पर लगी पाबंदी के कारण यह सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। भारतीय डायस्पोरा न केवल अपनी पहचान और परंपरा से जुड़े रहने के लिए भारत से सामान मंगाते हैं, बल्कि छोटे व्यापारिक स्तर पर भी उनका भारत के साथ सीधा संबंध होता है। अब उन्हें स्थानीय बाजार या तीसरे देशों से महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ेगा। यह स्थिति भारत-प्रवासी संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती है। साथ ही, जो छात्र और पेशेवर विदेशों में रहते हैं, वे भी अपने परिजनों से भेजे जाने वाले छोटे गिफ्ट्स और आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहेंगे। इससे भारतीय डायस्पोरा में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है, और दीर्घकाल में भारत सरकार पर इस निर्णय को पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर भारत का पहला रिएक्शन-25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए डाक सेवा (पोस्टल सर्विसेज)बंदभारत की ई-कॉमर्स कंपनियां, कई स्टार्टअप्स अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं,अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर को डाक सेवाओं या लॉजिस्टिक चैनलों से पूरा करतेहैं,उन पर असर पड़ेगा भारत का अधिकतम निर्यातक एमएसएमई क्षेत्र, यानें कपड़ा, हस्तशिल्प,ज्वेलरी,आयुर्वेदिक उत्पाद और छोटे पैमाने के तकनीकी उपकरण जैसे क्षेत्र संकट में पढ़ने की संभावना हैं।

रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च हुई, जानें कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स

रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट देश में रेनो की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काइगर की बिक्री की जाती है। रेनो ने इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी के नए वर्जन में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। कैसे फीचर्स दिए हैं। क्या कीमत है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में देश में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स और इंजन के साथ अपने उत्पादों की बिक्री की जाती है। रेनो की ओर से भी इस सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली काइगर के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई Renault Kiger Facelift

रेनो की ओर से भारत में काइगर को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को रेनो की ओर से 24 अगस्त को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है।

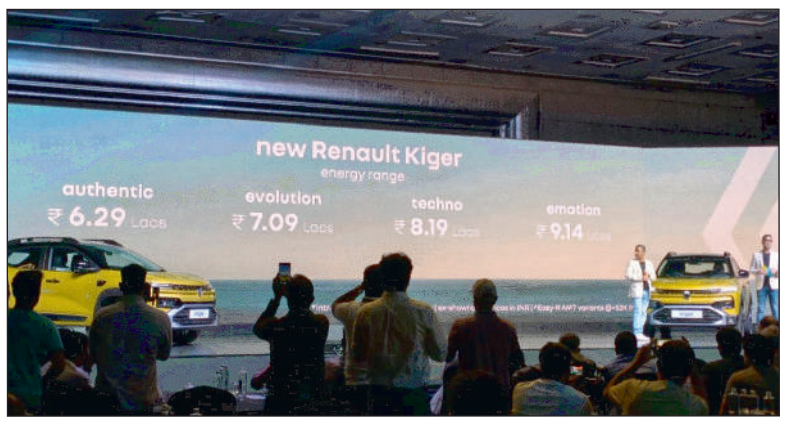

क्या हुए बदलाव

निर्माता की ओर से काइगर फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए हैं। इसके एक्सटीरियर के साथ ही इंटीरियर में भी कई बदलावों को किया गया है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स को भी दिया गया है। साथ ही इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट्स, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले जैसे फीचर्स को भी दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

रेनो की ओर से इस एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया गया है। इसमें पहले की ही तरह एक लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड और टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। जिससे इसे 72 और 100 पीएस की पावर और 96 और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन को मैनुअल, एएमटी (AMT) और सीवीटी (CVT) ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ पेश किया गया है।

कितनी है कीमत

रेनो की काइगर फेसलिफ्ट को भारत में 6.29 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.29 लाख रुपये है।

किनसे है मुकाबला

रेनो की ओर से भारत में काइगर को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite, Tata Punch, Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Syros, Kia Sonet जैसी एसयूवी के साथ होता है।

रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट आज होगी लॉन्च, जानें क्या होंगे बदलाव, कितनी हो सकती है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग रहती है। निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। रेनो की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर काइगर की बिक्री की जाती है। आज इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आज लॉन्च होगी Renault Kiger Facelift

रेनो की ओर से भारतीय बाजार में काइगर की बिक्री की जाती है। निर्माता इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को आज भारत में लॉन्च कर देगी।

क्या होंगे बदलाव

जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में ज्यादातर बदलाव कॉस्मैटिक होंगे। इसके इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इसके डिजाइन में भी कुछ बदलावों को किया जा सकता है।

मिलेंगे नए फीचर्स

रेनो की ओर से काइगर फेसलिफ्ट में Renault Triber की तरह, इसमें नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल, नए बंपर, पतली हेडलाइट्स और एक LED DRL स्ट्रिप मिल सकती है। इसके पीछे की तरफ नई LED टेल लैंप्स के साथ C-आकार की टेल लाइट्स दिए जा सकते हैं। साथ ही इसके डैशबोर्ड के लेआउट में भी कुछ मामूली बदलाव होने की उम्मीद है। नए फीचर्स के रूप में -इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में दिए जा सकते हैं।

कितना दमदार इंजन

निर्माता की ओर से इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहले की तरह ही एक लीटर की क्षमता का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। इस इंजन को मैनुअल, एएमटी (AMT) और सीवीटी (CVT) ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ पेश किया जाएगा।

किनसे है मुकाबला

रेनो की ओर से काइगर को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Nissan Magnite, Tata Punch, Kia Sonet, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी से मुकाबला होता है।

मारुति सुजुकी XL6 के सीएनजी वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद देनी होगी कितनी ईएमआई, जानें डिटेल

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के जरिए Maruti XL6 की बिक्री की जाती है। इस छह सीटों वाली एमपीवी को पेट्रोल के साथ ही CNG इंजन के विकल्प के साथ भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इस एमपीवी के सीएनजी वर्जन को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti XL6 CNG Price

मारुति की ओर से छह सीटों वाली एमपीवी के तौर पर XL6 की बिक्री की जाती है। निर्माता इस एमपीवी को CNG के साथ भी ऑफर करती है। इसके CNG वेरिएंट को मारुति की ओर से 14.77 लाख रुपये की ऑन रोड कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 1.30 लाख रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ ही करीब 41 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस एमपीवी के लिए टीसीएस चार्ज और अन्य चार्ज के तौर पर 17485 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 14.77 लाख रुपये हो जाती है।

2 लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर Maruti XL6 के CNG वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.77 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 12.77 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 20549 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 12.77 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20549 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti XL6 के CNG वेरिएंट के लिए करीब 4.49 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 19.26 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Maruti Suzuki की ओर से XL6 को एक एमपीवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Ertiga, Renault Triber, Kia Carens Clavis जैसी बजट एमपीवी के साथ होता है।

इस हफ्ते लॉन्च होने को तैयार नए स्कूटर और मोटरसाइकिल , इंडिया, एथर से लेकर टीवीएस तक कर रहे हैं तैयारी

आगामी दोपहिया वाहन लॉन्च देश में कई वाहन निर्माताओं की ओर से नए वाहनों को पेश और लॉन्च किया जाता है। अगस्त के नए हफ्ते में किस वाहन निर्माता की ओर से किस तरह के वाहन को किस सेगमेंट में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। किस तारीख को इनको लॉन्च किया जा सकात है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई तरह के स्कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। कई निर्माताओं की ओर से इन दोनों सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। अगस्त के नए हफ्ते में किस निर्माता की ओर से किस सेगमेंट में कौन से स्कूटर और मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Indian मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च

प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता इंडियन की ओर से भारतीय बाजार में 25 अगस्त को चार से पांच नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इन मोटरसाइकिल में अलग अलग जरुरत के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल होंगी, जिनमें INDIAN SCOUT SIXTY CLASSIC, INDIAN SCOUT SIXTY BOBBER, Indian Sport Scout SIXTY, INDIAN SUPER SCOUT और INDIAN 101 SCOUT शामिल हैं।

TVS लाएगी नया स्कूटर

टीवीएस मोटर्स भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह 28 अगस्त को नए स्कूटर को लॉन्च करेगी। यह स्कूटर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में होगा और इसका नाम TVS Orbiter हो सकता है। इसमें किस तरह की क्षमता की बैटरी और मोटर दी जाएगी, किस तरह के फीचर्स और रेंज को दिया जा सकता है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

Ather भी करेगी लॉन्च

30 अगस्त को एथर अपना एथर डे मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान निर्माता की ओर से नए इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सकता है। कुछ दिनों से निर्माता की ओर से नए स्कूटर स्कूटर प्लेटफॉर्म की झलक सोशल मीडिया पर टीजर जारी कर दी जा रही है। यह दिखाई देने में तो मौजूदा एथर 450 के प्लेटफॉर्म की तरह लग रहा है लेकिन इसमें एथरस्टेक के कुछ पार्ट्स के साथ ही अपडेटेड पावरट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया होगा। इसके साथ ही उम्मीद है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट वर्जन को निर्माता की ओर से इस मौके पर पेश किया जा सकता है।

माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, जानें डिटेल

होंडा एलिवेट बनाम मारुति ग्रैंड विटारा भारत में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में होंडा की ओर से एलीवेट की बिक्री की जाती है। वहीं दूसरी ओर मारुति सुजुकी की ओर से भी इस सेगमेंट में बिक्री के लिए ग्रैंड विटारा को उपलब्ध करवाया जाता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदें। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। होंडा की ओर से इस सेगमेंट में एलीवेट को ऑफर किया जाता है तो मारुति सुजुकी की ओर से भी इसी सेगमेंट में विटारा की बिक्री की जाती है। इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी (Honda Elevate Vs Maruti Grand Vitara) को खरीदना ज्यादा बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Elevate Vs Maruti Grand Vitara फीचर्स

होंडा Elevate में एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप, फ्रंट और रियर बंपर पर सिल्वर स्किड गार्निश, 16 और 17 इंच व्हील्स, शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर मिरर, सिंगल पेन सनरूफ, बेज और ब्लैक इंटीरियर, स्टेयरिंग माउंटिड ऑडियो कंट्रोल्स, स्मार्ट की, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्टॉर्ट/स्टॉप, पिंच गार्ड ड्राइवर पावर विंडो, पावर एडजस्टेबल मिरर, फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मैक्स कूल मोड, रियर एसी वेंट, पीएम 2.5 केबिन एयर प्यूरीफायर, ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टेयरिंग व्हील, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, 60-40 स्प्लिट सीट, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंबिएंट लाइट्स, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

वहीं मारुति ग्रैंड विटारा में एलईडी लाइट्स, फॉलो मी हैडलैंप, शॉर्क फिन एंटीना, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलैस चार्जर, पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट, आर्किमिस साउंड सिस्टम, सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Honda Elevate Vs Maruti Grand Vitara इंजन

Honda Elevate एसयूवी में कंपनी की ओर से इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 121 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जाते हैं। कंपनी के मुताबिक एसयूवी को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक लीटर में 15.31 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और इसके सीवीटी वर्जन का माइलेज 16.92 किलोमीटर प्रति लीटर तक है।

वहीं मारुति ग्रैंड विटारा में पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक के विकल्प के साथ इंजन को दिया जाता है। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 92.45 पीएस से लेकर 103.06 पीएस की पावर और 122 से 136.08 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लाया जाता है और इसे एक लीटर में 19.38 किलोमीटर से 27.97 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

Honda Elevate Vs Maruti Grand Vitara कीमत

होंडा एलिवेट एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 11.91 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.41 लाख रुपये तक है।

वहीं मारुति ग्रैंड विटारा की एक्स शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये तक है।

समाज 'सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का भी संकट है

विजय गर्ग

मातृभाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती। उससे व्यक्ति के जीवन की शुरुआत के संस्कार जुड़े होते हैं, इसलिए वह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए आत्मिक और मानसिक संबल भी होती है। शायद इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा था- 'निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।' यानी अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार र की । उन्नति का आधार है। आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने भारत में लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की थी, तो तो उसका भी उद्देश्य यही था कि था कि भारतीयों से उनका सांस्कृतिक और भाषाई गौरव छीन लिया जाए, ताकि ब्रिटिश शासन को उसके । की पूर्ति के लिए पढ़े-लिखे सेवक मिल सकें। कहना नहीं होगा कि अंग्रेज अपनी इस नीति में बहुत हद तक सफल भी रहे थे। आजादी के बाद भी समाज में ऐसा वर्ग आज भी अभिजात्य होने के गर्व में जीता है, जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ही सार्थक जीवन का सोपान समझता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि ऐसी 'कई भारतीय भाषाएं हैं जो सीधे तौर पर रोजगार से नहीं जुड़ी होने के कारण धीरे-धीरे चलन से बाहर हो गई और आज उनका उपयोग करने वाले लोग कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जवां, शोम्पेन, वहीं मणिपुर की एमोल, कोइरेन, तराओ; हिमाचल प्रदेश की बधाती, हंदुरी, पंगवाली, ओड़ीशा की मंडा, परजी, पेंगो; कर्नाटक की कोरोगा, कुरूबा और इसी तरह असम की तेई तेई रा एवं एवं तेई तेई रोग ऐसी ही भाषाएं हैं। यूनेस्को की सूची में ऐसी 197 भारतीय भाषाएं हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही आधुनिक समाज 'सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का भी संकट है। संकटग्रस्त भाषाएं श्रुति परंपरा के कारण किसी तरह से कुछ और समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में हो । भी हैं, तो प्रचलन से बाहर होने के कारण उनकी लिपि को पढ़ने और समझने वाले नहीं मिलते। राजस्थानी भाषा के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता सकता है। इस भाषा को । इस भाषा को बोलने वालों की संख्या आज । करोड़ों में है, लेकिन प्राचीन राजस्थानी लिपि मुंडिया को पढ़ने और समझने वाले लोग आज गिनती के हैं।

दरअसल, आजादी के बाद तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देश की एकता बचाए रखने लिए सेठ गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थानी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का आग्रह किया। राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए राजस्थानियों ने इस भावनात्मक आग्रह को स्वीकार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे मुंडिया लिपि चलन बाहर हो गई और उससे परिचित लोग घटते चले गए। आज जब राजस्थानी भाषा 1 के समर्थ भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करते हैं तब तब विरोधियों। द्वारा भी दिया जाता है कि इस भाषा ★ कि इस भाषा की पृथक लिपि ही नहीं है। भाषा के सवाल राजनीतिक' 'सवाल के तौर पर भी बार-बार इस्तेमाल किया गया है। भाषा से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव क्या रूप ले सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण है। वर्ष 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो उन्होंने गंगा और

सिंधु की धरती को बांट दिया। तब ढाका की तरफ वाले हिस्से यानी पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होना बेहतर लगा। मगर धीरे-धीरे पूर्वी बंगाल के लोगों का मोह टूटने लगा। इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया। मगर जब वहां की भाषा को विस्थापित करने की कोशिश की गई, तो जनता के सब्र का बांध टूट गया। फिर हिंसा फैली और भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र का उदय हुआ।

भारत में भाषाएं बार-बार संघर्ष का मुद्दा बनती हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी बांग्लाभाषियों के हितों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसे बांग्ला भाषा अभियान नाम दिया गया है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की सुगबुगाहट हुई थी। दक्षिण भारत में तो हिंदी विरोध के कई आंदोलन हुए। उत्तर और पूर्वी के नाम पर राज्यों के पुनर्गठन किए गए हैं।। भारत में भाषा के नाम पर भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था मद्रास राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों से बना। दरअसल, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की बात जब संविधान सभा में बार-बार उठी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1948 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके घर अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस पर जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली एक समिति बनाई गई। इस समिति ने भी अपनी सिफारिशों में आयोग की बात का समर्थन किया। बाद तेलुगू [भाषियों आंदोलन कर दिया। अक्तूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामालू [ने तेलुगू भाषी आंदोलन के तहत अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू र दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आजाद भारत मैं ही बंबई राज्य का राज्य का विभाजन मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर किया गया। वर्ष 1966 में असम से नगालैंड, वर्ष 1966 में ही पंजाब से हरियाणा बनने जैसी घटनाओं के पीछे भी भाषा ही आधार रही। भी मैथिली, ,भोजपुरी, मुंडारी, अंगिका और राजस्थानी बोलने वाले लोग अपनी-अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए चिंतित हैं और उन्हें संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन भाषाओं के समर्थकों का कहना है कि उनकी भाषा को संवैधानिक संरक्षण या मान्यता नहीं' 1 मिली, तो नई पीढ़ी अपनी भाषा से दूर होती जाएगी। इस तरह उनकी भाषा के अस्तित्व पर संकट बढ़ता चला जाएगा। मगर यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त 197 भाषाओं की सूची में शामिल भूमिज भाषा के समर्थकों ने अपने अनूठे संकल्प से यह ह साबित कर दिया कि भाषा के सबसे बड़े संरक्षक संरक्षक उसके समर्थक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र यानी झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भूमिज' भूमिज समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। इस समाज के कुछ जागरूक लोगों ने वर्ष 3 में अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ करने की ठानी और क्षेत्र में ऐसे स्कूल खोले, जहां लोगों को अपनी भाषा का शिक्षण दिया। नई पीढ़ी को अपनी भाषा भाषा से जोड़ने के लिए पढ़ाया भी। रूस के महान उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोएव्स्की ने एक स्थान पर लिखा है- 'यदि तुम हो दूसरे तुम्हारा सम्मान करें, तो इसकी

सबसे पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरत यह है कि तुम स्वयं अपने आप का सम्मान करो।' भूमिज समुदाय के लोगों ने अपने संकल्प से यह साबित किया है कि अपनी मातृभाषा के संरक्षण के लिए किसी का मुंह ताकने से अच्छा है कि हम स्वयं अपने संकल्पों को हौसलों का आसमान दें।

परमार को भारत रत्न

हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव कल हिमाचल विधानसभा में पारित किया गया जो स्वागत योग्य है। हालांकि इसे बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था। हिमाचल के अस्तित्व में आने से लेकर पूर्ण राज्यत्व तक श्रद्धेय परमार जी का योगदान अविस्मरणीय है। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचल वासियों के दिलों में आज भी जितने गहरे डॉक्टर परमार बैठे हैं उतने शायद कभी कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के दिलों में नहीं बैठ पाए अन्यथा पिछले 55-60 वर्षों से सत्ता में काबिज रही पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकती थी? उनके पैतृक गांव को भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में एक विशाल विरासत के रूप में विकसित कर सकती थी, स्कूलों में उन पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करवाकर विद्यार्थियों को अपनी मिट्टी के इस सपूत को पढ़ाया जा सकता था। उन पर अच्छी फिल्में बन सकती थी और दो-चार पुस्तकें उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक सफर पर निकल सकती थी। और भी बहुत कुछ इस सपूत के लिए किया जा सकता था, यदि प्रशासन और सरकारों की पूर्ण प्रतिबद्धता रहती। कुछ जो उनके नाम पर हुआ है, वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। हमारे प्रिय साथी और उप मुख्यमंत्री जी कल जब विधानसभा के प्रस्ताव पर जोर-शोर से बोल रहे थे, हमारा सीना गर्व से फूल रहा था। पर यह भी याद आ रहा था कि वे संस्कृति विभाग के मंत्री जी हैं और भाषा विभाग का एकमात्र डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राज्य सम्मान पिछले बीस सालों से बंद पड़ा है। थोड़ा सा दुःख हुआ कि किस मुंह से ये लोग साठ सालों बाद परमार जी के लिए इतने चिंतित हो गए, जबकि जो हिमाचल में ये लोग कर सकते थे, उसे तो कभी तरजीह नहीं दी।

हां, रिज पर उनकी एक प्रतिमा लगा कर और वर्ष में उनकी जयंती मनाकर पल्ला अवश्य झाड़ते रहे। क्षमा चाहूंगा मुकेश अग्निहोत्री जी से कि कांग्रेस सरकार चाहती तो अपने हीरो को आसमान दे देती, पर आपका विभाग तो अब तक परमार पर कोई बेहतरीन पुस्तक भी न निकाल पाया.और राज्य सम्मान ही बंद कर दिया। मेरा तो सिर शर्म से झुक जाता है, पता नहीं आपका झुकता होगा कि नहीं? और परमार की जयंती पर यदि हमारे सबसे काबिल साहित्य और संस्कृति प्रेमी आदरणीय संस्कृति सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राकेश कंवर जी अध्यक्षता कर रहे हो तो मेरे जैसा छोटा सा परमार प्रेमी डर-सहम कर या तो जाएगा ही नहीं, या चुप्पी लगा लेगाक्योंकि कंवर जी ने जिस उत्साह से भाषा संस्कृति विभाग का उत्तरदायित्व संभाला था, हम सभी को उनका स्नेह मिलना शुरू हुआ था, पता नहीं बहुत जल्दी वह किन किन 'प्राकृतिक आपदाओं' के बीच फंस कर रह गया। गलती से दो साल पहले परमार जयंती पर मैंने दो-चार सवाल पूछ लिए थे, यही जो ऊपर लिखे हैं, वे इतने असहज हो गए कि बीस मिनट तक इसी पर स्पष्टीकरण देते रहे। उसके बाद कभी मेरी भाषा विभाग और अकादमी के कार्यक्रमों में जाने की 'हिम्मत' नहीं हुई। वैसे भी हम पहाड़ियों के दिल होते ही कितने बड़े हैं, हमें आंखें दिखा कर ही चुप करवा दिया जाता है।

खैर, आज कांग्रेस सरकार और आदरणीय कंवर साहब की कृपा से रिज पर परमार साहब की एक प्रतिमा और एक जयंती तो सही सलामत है, वह क्या भारत रत्न से कम है? उधर शायद कोई विधायक या मंत्री हिमाचल भाषा विभाग और अकादमी के लिए भी

शहरी विकास में जानवरों की उपेक्षा भारी

सरकारी मशीनरी में समस्याओं के समाधान को लेकर जंग लगी हुई है। यह मशीनरी तभी हरकत में आती है, जब कभी अदालतों के निर्देश आते हैं। देश में जब तक आधारभूत ढांचे से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आवारा जानवरों से मुक्ति के अभियान कागजी साबित होंगे। शहरी विकास की परिभाषा फिर से तय करने की जरूरत है। शहरों को सुनियोजित विकास को लेकर बनाए मास्टर प्लान में पशुओं का भी ख्याल रखना होगा

विकास की भौतिक चकाचौंध ने इनसान को जानवर बनाने में कसर नहीं छोड़ी। इसका खामियाजा जानवर भी भुगत रहे हैं। सहअस्तित्व के बजाय पालतू जानवर सिरदर्द समझे जाने लगे हैं। जानवर चाहे पालतू हों या जंगली, सब पर इनसान की वक्रदृष्टि पड़ चुकी है। जानवर की जान आफत में हैं। सुविधाओं के लिए की गई शहरों की बसावट के दौरान यह सोचा ही नहीं गया कि सदियों मेरे दोस्त मेरे हमदम की तरह साथ निभाने वाले पालतू जानवर कहां रहेंगे। धार्मिक आस्था के नाम पर लकीर के फकीर बने लोगों ने जानवरों का प्राकृतिक आवास छीन कर उन्हें पराश्रित शहरी बना दिया। शहरों में रहने वाले पालतू जानवर प्राकृतिक तौर से जीवित रहने के तौर-तरीके भूल कर पूरी तरह इनसानों पर आश्रित हो गए हैं। इनकी संख्या बढने से अब टकराहट की नौबत आ गई है। इनसान और जानवर का यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बहस का वैधानिक केंद्र बना हुआ है। देश की शीर्ष अदालत को तय करना है कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नए सिरे से क्या निर्देश दिए जाएं। देश में शायद यह पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट लोगों की जनभावनाओं के मद्देनजर अपने किसी निर्णय पर फिर से सुनवाई के लिए तैयार हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर में तीखी प्रतिक्रियाएं जताई थी। इसके बाद कोर्ट नए सिरे से अपने ही फैसले पर पुनर्विचार को राजी हुआ। देशभर के लोग कैसे कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं। साल 2018 में देशभर में कुत्तों के काटने के 75.7 लाख मामले सामने आए।

कोविड के दौर में इसमें गिरावट हुई और 2020 में 47.6 लाख और 2021 में 32.4 लाख मामले आए। लेकिन 2023 से ऐसे मामलों का ग्राफ फिर बढना शुरू हुआ। इस साल 30.5 लाख मामले सामने आए और 2024 में यह बढ़कर 37.2 लाख पहुंच गया। आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों के काटने से रैबीज के कारण होने वाली मौतों का ग्राफ बढ़ा है। वर्ष 2022 में इससे 21 मौतें हुई थीं, लेकिन 2023 में आंकड़ा बढ़कर 50 पर पहुंच गया। वर्ष 2024 में इससे 54 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कुत्तों के काटने की सर्वाधिक घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में 56538 मामले सामने आए। 53942 मामलों के साथ दूसरे पायदान पर गुजरात और 48931 केसेज के साथ तमिलनाडु था। वहीं कर्नाटक में 39500 मामले और बिहार में 34000 केस सामने आए। दरअसल दिल्ली और राजधानी परियोजना क्षेत्र में ही नहीं कुत्ते सहित अन्य आवारा पशुओं की समस्या देश में सिरदर्द बन गई है। जब कभी अदालत या सरकारी मशीनरी इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है, तब पशु प्रेमी विरोध पर उतर आते हैं। उनका विरोध भी नाजायज नहीं कहा जा सकता। आवारा जानवरों की समस्या सरकारी तंत्र की देन है। आधे-आधे संसाधनों से ऐसे अभियान हमेशा से विवादों में रहे हैं। सरकारी तंत्र की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार आवारा पशुओं की रोकथाम में सबसे बड़ी बाधा रही है। विकास के बुनियादी ढांचे में जानवरों का ख्याल ही नहीं रखा गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन मालिक है, जिसके पास 535.78 मिलियन पशुधन आबादी है। कुल मवेशी आबादी 192.49 मिलियन (पशुधन जनगणना 2019) है। साल 2019 की गणना के हिसाब से देश में 2.03 करोड़ लावारिस पशु हैं। इनके हमले से हर दिन तीन व्यक्तियों की मौत होती है। पिछले 3 साल में 3800 लोगों ने जान गंवाई। देश के महानगरों में सडक़ दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण आवारा कुत्ते, गाय और चूहे जैसे जानवर हैं। यह बात अग्रणी टेक-फस्ट बीमा प्रदाता कंपनी एको की एको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, देश में सडक़ दुर्घटनाओं का मुख्य कारण जानवर थे, खासकर चेन्नई में जानवरों के कारण सबसे अधिक तीन प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं।

सुपरहैवी केमिस्ट्री आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित कर सकती है

विजय गर्ग

सुपरहेवी रसायन पूरी तरह से आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। जबकि सुपरहेवी तत्वों का अध्ययन चुनौतीपूर्ण है और आवधिक रुझानों से दिलचस्प विचलन को प्रकट करता है, ये तत्व अभी भी मौलिक रूप से आवधिक कानून के अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करते हैं। आवधिक कानून क्या है? आवधिक कानून में कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य हैं। यही कारण है कि आवर्त सारणी के एक ही समूह (ऊर्ध्वाधर स्तंभ) में तत्व आम तौर पर समान गुणों को साझा करते हैं, क्योंकि उनके पास समान संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी की व्यवस्था परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित है। भारी तत्व और सापेक्ष प्रभाव सुपरहेवी तत्व 103 (लॉरेनशियम) से अधिक परमाणु संख्या वाले होते हैं। इन तत्वों के रसायन विज्ञान की भविष्यवाणी मुख्य रूप से सैद्धांतिक गणनाओं के माध्यम से की जाती है, क्योंकि वे संश्लेषित और अध्ययन करने के लिए बेहद मुश्किल हैं। उनकी केमिस्ट्री इतनी आकर्षक होने का कारण सापेक्ष प्रभाव है। प्रकाश की गति

के करीब गति से आगे बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए सापेक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उच्च परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के लिए, नाभिक का मजबूत सकारात्मक आवेश आंतरिक-खोल इलेक्ट्रॉनों को इन उच्च गति पर ले जाने का कारण बनता है। इसके दो बड़े परिणाम हैं:

इलेक्ट्रॉन मास वृद्धिः इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बढ़ता है, जिससे उनके ऑर्बिटल्स अनुबंध करते हैं।

कक्षीय विभाजनः इलेक्ट्रॉन कक्षों के ऊर्जा स्तर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे हल्के तत्वों के लिए उपयोग किए जाने वाले सरल शेल मॉडल का टूटना हो सकता है। इन प्रभावों के कारण तत्वों को अपने लाइटर कॉन्गेनर्स से सरल एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में अलग व्यवहार करने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, सापेक्षता प्रभाव समूह 11 में एक तत्व का कारण बन सकता है जो पी-ब्लॉक तत्व की तरह अधिक व्यवहार करता है, या समूह 12 में एक तत्व का कारण बनता है जो एक अप्रत्याशित ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित क्यों नहीं किया जाएगा जबकि सापेक्षता प्रभाव आकर्षक विचलन का परिचय देते हैं, वे मौलिक रूप से अंतर्निहित इलेक्ट्रॉन खोल संरचना को नहीं बदलते हैं जो आवधिक कानून को निर्धारित करता है। रासायनिक गुण अभी भी मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक कार्य है। सुपरहेवी तत्वों में अभी भी प्रोटॉन की एक परिभाषित संख्या है, जो आवधिक तालिका पर उनकी स्थिति निर्धारित करती है। एक पूर्ण पुनर्व्यवस्था के बजाय, हम देखने की अधिक संभावना हैः

रुझानों का कमजोर होनाः एक समूह के भीतर रुझान कम स्पष्ट या उल्टे भी हो सकते हैं।

विसंगतिपूर्ण व्यवहारः कुछ तत्व अपने समूह के लिए विशिष्ट नहीं ऑक्सीकरण स्थिति या रासायनिक संपत्ति प्रदर्शित कर सकते हैं।

स्थिरता के द्वीपः रसायन विज्ञान इन तत्वों के लिए एक स्समूहस्र को परिभाषित करने के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने के लिए काफी विचलित हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन काउंट के आधार पर तालिका की समग्र संरचना बनी रहेगी। संक्षेप में, सुपरहेवी रसायन विज्ञान सरल आवधिकता की सीमाओं को प्रकट करता है, लेकिन यह परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आवधिक तालिका के मौलिक संगठनात्मक सिद्धांत को अमान्य नहीं

संयुक्त परिवार में सैकड़ों समस्याएं होती हैं, लेकिन समाधान भी यहीं मिलते हैं।

विजय गर्ग

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन हर परिवर्तन प्रगति नहीं होता । हर पीढ़ी अपने समय के अनुरूप बदलाव लाती है। अगर यह बदलाव संस्कारों की नींव पर आधारित हो, तो इसे सतत प्रगति कहा जाएगा, मगर जब परिवर्तन का यह प्रवाह मूल्यहीन और दिशाहीन होने लगता है, तो वह मात्र उच्छृंखल विद्रोह का रूप ग्रहण कर लेता है। आज की युवा पीढ़ी जिस तीव्रता से पारंपरिक सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, वह केवल स्वतंत्रता का उत्सव न होकर एक गहन प्रश्न बनकर उभरता है कि क्या यह सीमा लांघना वास्तविक बौद्धिक मुक्ति है या फिर केवल पश्चिम प्रेरित मोहभंग ?

संस्कृति केवल अनुष्ठानों और परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि वह एक जीवन - दृष्टि है, जो समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। जब युवा पीढ़ी इसे बंधन का प्रतीक मानने लगती है, तो वह इस तथ्य को विस्मृत कर देती है कि ये तथाकथित 'बंधन' ही सामाजिक समरसता और सह अस्तित्व की संरचना के आधार स्तंभ हैं। पाश्चात्य समाजों में जहां अक्सर 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ सामाजिक, पारिवारिक और

सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों से विमुक्ति समझा जाता है, वहीं भारतीय जीवन- दृष्टि में स्वतंत्रता का मर्म आत्मनियंत्रण, कर्तव्यपरायणता और मर्यादा में निहित है।

एक समय था जब घर के बड़े-बुजुर्ग अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा करते थे कि संयुक्त परिवार में सैकड़ों समस्याएं होती हैं, लेकिन समाधान भी यहीं मिलते हैं। आज समस्या वही है, समाधान भी है, बस अब समाधान 'रिटायरमेंट होम' कहलाता है। कभी कहे जाने वाले 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' जैसे कथन मोबाइल की किसी पुरानी तस्वीर की तरह रह गए हैं, जिसे देखकर

लोग हंसते हैं और कहते हैं कि 'ये सब अब नहीं चलता !' संयुक्त परिवारों की वे जड़ें, जिनमें परिवार रूपी वट वृक्ष सांस लेता था, अब 'फ्लैट संस्कृति' में गमले के

पौधे बन गई हैं। ये सजावटी तो हैं, लेकिन छाया नहीं देतीं । स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप आत्मविकास से जुड़ा होता है, अनुशासन के त्याग से नहीं । आधुनिकता के नाम पर अगर व्यक्ति नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख हो जाता है, तो वह न तो स्वयं को उन्नत कर सकता है और न ही समाज को । नैतिकता अब एक 'वैकल्पिक अवधारणा' बन गई है और संस्कार उस पाठ्यपुस्तक की तरह, जिसे परीक्षा से एक दिन पूर्व पढ़ा जाता है और फिर साल भर भुला दिया जाता है । आधुनिकता ने भारतीय मानस को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है, जहां 'मर्यादा' पुरानी पगडंडी की तरह लगती है और 'स्वच्छंदता' किसी तेज रफ्तार राजमार्ग की तरह, भले ही उसमें दुर्घटनाओं की भरमार हो ।

नई पीढ़ी को चाहिए 'मुक्ति', पर वह यह तय करने में असमर्थ है कि मुक्त किससे होना है - समाज की अपेक्षाओं से या फिर स्वयं की जिम्मेदारियों से ? स्वतंत्रता का अर्थ अब इतना विस्तार पा चुका है कि अनुशासन उसमें डूबने लगा है। विवाह, जो एक पवित्र बंधन बन जाता है, अब केवल सुविधाजन्य अनुबंध के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे संबंधों का प्रचलन बढ़ रहा है, जिनमें विवाह को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण मानते हुए अस्वीकार किया जाता है । यह विचारणीय है कि क्या यह वास्तव में स्वतंत्रता है या फिर उत्तरदायित्वों से पलायन का एक सुसज्जित माध्यम ! जब विवाह में समर्पण और सह-अस्तित्व की भावना क्षीण होती है, तब समाज का संतुलन भी डगमगाने लगता एक समय था जब लोग परिश्रम से कमाते थे और संतोष से जीते थे। अब तो प्रचार यह बताते हैं कि हमारी खुशियां 'महंगी और सजावटी' होनी चाहिए। वैश्वीकरण ने समाज को एक ऐसे बहुराष्ट्रीय उपभोक्तावादी मंच में परिवर्तित कर दिया है, जहां पारंपरिक मूल्यों पर भारी छूट है और पाश्चात्य विचारधाराएं महंगी अलमारियों में सजी हुई हैं, जहां नई पीढ़ी चमक के आधार पर खरीदारी कर रही है । वे लोग खुद को ग्राहक समझते हैं। जबकि असली उत्पाद तो वे खुद ही हैं, जिनके समय, विचार और भावनाओं का व्यापार किया जा रहा है

प्रश्न यह नहीं है कि नई पीढ़ी प्रभावित हो रही है, प्रश्न यह है कि वह किस प्रकार और क्यों प्रभावित हो रही है। क्या यह प्रभाव आत्मसात करने योग्य है ? पाश्चात्य समाज में 'स्वतंत्रता' को सर्वोपरि माना जाता है जो भारतीय समाज की सामूहिक चेतना और व्यवस्था से कोसों दूर तक मेल नहीं खाता। वहीं भारतीय समाज में 'कर्तव्य' को उस स्वतंत्रता का आधार स्तंभ माना गया है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है- 'संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, और यदि आत्मा ही मर जाए, तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता ।' स्वामी विवेकानंद ने भी समाज की परंपरागत रूढ़ियों को चुनौती दी थी, पर वे भारतीयता के मूल तत्त्वों से विमुख नहीं हुए । वे मानवता के पुनरुत्थान के संवाहक बने, विनाश के नहीं। आज जब युवा 'स्वतंत्रता' के नाम पर परंपराओं का निस्तारण कर रहे हैं, तो यह आत्मावलोकन किया जाना चाहिए कि क्या वे मुक्त हो रहे हैं या केवल आत्महीनता के नए संजाल में फंस रहे हैं! क्या यह विद्रोह आत्मचिंतन से जन्मा है, या केवल पश्चिमी प्रभाव का अंधानुकरण है? सीमाओं का उल्लंघन तब सार्थक होता है, जब वह आत्मविकास और सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे, न कि मूल पहचान के विखंडन का । प्रश्न यह नहीं कि सीमाएं लांघी जाएं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें लांघने का उद्देश्य क्या है- विनाश या विवेकपूर्ण पुनर्निर्माण ?

बोतलबंद पानी पर अत्यधिक निर्भरता स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है

विजय गर्ग

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो 2060 तक दुनियाभर में प्लास्टिक कचरे की मात्रा तीन गुनी हो जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा बोतलबंद पानी से जुड़ा है, जिसके प्रबंधन और पुनर्चक्रण की दिशा में गंभीर होने की आवश्यकता है।

दरअसल शहरीकरण के विस्तार, भूमिगत जल में प्रदूषक की बढ़ती मात्रा, पर्यटन में वृद्धि और जीवनशैली में आए बदलाव के कारण बोतलबंद पानी की मांग और खपत तेजी से बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक वैश्विक बोतलबंद पानी के बाजार का आकार 509 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच सकता है। बोतलबंद पानी उस आबादी की प्यास बुझाने का आसान जरिया बन चुका है, जो बाहर घूमते समय या यात्रा के दौरान सुविधा और तुरंत उपलब्धता के कारण इसे प्राथमिकता देते हैं। कुछ दशक पहले तक लोग अपनी

प्यास सार्वजनिक चापानलों से आसानी बुझा लेते थे, मगर पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा ने उन्हें धीरे-धीरे बोतलबंद पानी पर अधिक निर्भर बना दिया है। हालांकि पानी की जिन बोतलों को हम आसानी से खरीदकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, उसके निर्माण, परिवहन और लैंडफिल से पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचता है। एक प्लास्टिक की बोतल बनाने में लगभग तीन लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके उच्च 'जल पदचिह्न' को दर्शाता है। वहीं, इसके निर्माण से लेकर बाजार के कोने-कोने तक पहुंचाने की प्रक्रिया में ईंधन की खपत भी होती है, जो न सिर्फ ऊर्जा स्रोतों पर दबाव डालती है, बल्कि वायु प्रदूषण का कारण भी बनती है। यही नहीं, प्लास्टिक की बोतल सामान्यतः एकल उपयोग में ही लाई जाती है और इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है। रीसाइक्लिंग प्रक्रिया तक न पहुंच पाने वाली बोतलें भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण में योगदान देती है। प्लास्टिक की बोतलों को सड़ने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, तब तक ये पारितंत्र और मानवता को गहरे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये टूटकर माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मृदा और जलस्रोत में समा सकते हैं, जिससे क्रमशः उत्पादित खाद्य पदार्थों और पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ, चिकित्सकों द्वारा प्लास्टिक की बोतल में लगातार पानी पीने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक घुलने का खतरा बढ़ जाता है।

बोतलबंद पानी पर अत्यधिक निर्भरता स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी जगह पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलें खरीदना और जल पुनर्भरण स्टेशनों से इसे रिफिलिंग करवाने की आदत पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से कुछ राहत ज दिला सकती है।

इन्दौर में एक स्कूल जो छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कारगार साबित है।

परिवहन विशेष न्यूज

इन्दौर में एक स्कूल जो छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कारगर बिरला ओपन माइंड्स प्रीस्कूल, स्कीम नं -140, इंदौर में स्थित है जहां हमारी अनुभवशील , उत्साही शिक्षकों की टीम बच्चों के विकास के लिए हमेशा तत्पर है, जो उनके व्यक्तिगत कौशल को प्रोत्साहित करती है।

स्कूल का संचालक श्री निलय जैन द्वारा किया जा रहा है।जिन्होंने बताया की बच्चों में के बौद्धिक क्षमता की भावना जगाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, उनका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ रचनात्मकता, सामाजिकता एवं उत्सुकता को जागृत करना है। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते पर अगर कुम्हार उन्हें अच्छे से मिट्टी को मिला कर जिस सांचे में ढाल देगा वह उसी के समान हो जाएंगे। निलय जैन ने बताया की बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना उन्हें अपनी सोच, भावनाओं को स्पष्ट एवं सही भाषा में व्यक्त करने के लिए सक्षम बनाएं और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय एवं रचनात्मक बनाना, बच्चों में अच्छी आदतें, स्वस्थ्य जीवन शैली एवं स्वच्छता के नियम विकसित करना तो है ही साथ साथ, माता-पिता एवं समुदाय को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाना . विद्यालय का संक्षिप्त विवरण बिरला ओपन माइंड्स प्रीस्कूल , इंदौर में बच्चों की अनूठी क्षमताओं का सम्मान करते हुए, उत्साही और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाता है। यहां सहज एवं आनंदपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से यहाँ बालकों को उनकी रुचि के अनुसार विविध गतिविधियाँ, खेल, कहानियाँ और आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ सिखाई जाती हैं, जिससे वे अपनी जीवन कौशल, वैश्विक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को उत्कृष्ट रूप में विकसित कर सकें। यहाँ का वातावरण उत्साहजनक, सहयोगी तथा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त है।

सामाजिक और पांथिक सौहार्द के लिए जरूरी है अंतर-धार्मिक संवाद

डॉ. नीरज भारद्वाज

तेज़ी से बदल रही दुनिया में धार्मिक विविधता, हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। हम देखते हैं कि लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, यहूदी आदि जिनकी अपनी-अपनी मान्यताएँ, परंपराएँ और आचार व व्यवहार होते हैं। हालांकि ये धर्म ऊपर से अलग दिखते हैं लेकिन ये अक्सर शांति, प्रेम, दया और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे साझा मूल्यों के आधारभूत संरचना पर ही आरूढ़ होते हैं। फिर भी, गलतफहमियों, जानकारी की कमी, विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह और कभी-कभी राजनीति के कारण धर्म संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे में अंतर-धार्मिक संवाद का महत्व बढ़ जाता है। यह हमें एक-दूसरे को समझने और शांति से साथ रहने में मदद करता है।

अंतर-धार्मिक संवाद का अर्थ है - अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच खुला और सम्मानजनक संवाद। यह किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की बहस नहीं है बल्कि यह सुनने, समझने और सीखने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य, आपसी सम्मान बढ़ाना, नफरत कम करना, और ऐसा समाज बनाना जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यहां यह भी समझना चाहिए कि जब परमात्मा एक है तो उसने जिस किसी को बनाया वह सब उसी की संरचना है। उन संरचनाओं में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो परमपिता को ही हानि पहुंचती है। इसलिए आपसी संवाद से ही यह तय होगा कि आधिर ईश्वर और उसके द्वारा रचा गया संचार कितना व्यापक और संवेदनशील है।

धार्मिक मतभेदों के कारण अक्सर अविश्वास, घृणा और हिंसा देखी गई है। हम अकसर सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक तनावों और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के बारे में सुनते हैं जो प्रायः अन्य धर्मों के प्रति गलतफहमियों पर आधारित होते हैं। जब व्यक्ति अन्य धर्मों के बारे में नहीं जानते तो झूठी बातों पर विश्वास करना या नफ़रत से प्रभावित होना आसान हो जाता है। अंतर-धार्मिक संवाद गलत धारणाओं की दीवारों को तोड़ता है, समुदायों के बीच मित्रता बनाता है, एक-दूसरे के विश्वास और मूल्यों को समझने में मदद करता है और शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय जैसे सामान्य लक्ष्यों पर साथ मिलकर काम करने का रास्ता खोलता है। इससे शांति और एकता को बढ़ावा मिलता है और अज्ञान या डर से होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।

अंतर-धार्मिक संवाद का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे यह पता चलता है कि सभी धर्मों की शिक्षाओं में कई समानताएँ हैं। अधिकतर धर्म शांति और अहिंसा, करुणा और दान, सत्य और ईमानदारी, बुजुर्गों का सम्मान, गरीबों की सेवा, क्षमा और विनम्रता की बात करते हैं। जैसे - हिंदू धर्म 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात करता है (सारा संसार एक परिवार है), इस्लाम रहमा (दया) और सलाम (शांति) पर ज़ोर देता है, ईसाई धर्म अपने पड़ोसी से प्रेम करो सिखाता है, बौद्ध धर्म अहिंसा और सचेतनता का समर्थन करता है, सिख धर्म सर्वत दा भला (सबकी भलाई) की बात करता है और जैन धर्म अपरिग्रह (त्याग) और

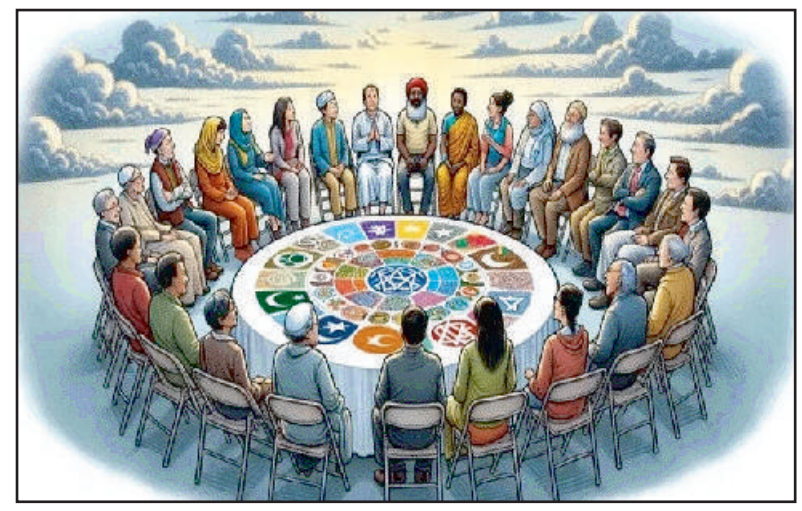

शांतिपूर्ण जीवन पर बल देता है। जब लोग धर्म की सीमाओं से परे बात करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे उतने अलग नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था, या बताया जाता है। यह एक साझा मानवता की भावना को जन्म देता है, जो साम्प्रदायिक सौहार्द की नींव है।

हम विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को कई तरीकों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी सम्मानपूर्वक और तथ्यात्मक रूप से दी जानी चाहिए। जब युवा सभी विश्वासों की सुंदरता को समझते हुए बड़े होते हैं तो वे दूसरों से नफ़रत नहीं करते। विभिन्न धर्मों के लोगों को साथ लाकर त्योहारों, संगोष्ठियों या कार्यशालाओं का आयोजन समझ को बढ़ाता है। एक-दूसरे के त्योहार मिलकर मनाना खुशी और दोस्ती को बढ़ाता है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि के धर्मगुरुओं का समाज पर बड़ा प्रभाव होता है। जब वे एकजुटता की बात करते हैं, तो लोग सुनते हैं। वे अपने अनुयायियों को सहिष्णुता और शांति की राह दिखा सकते हैं। मीडिया नफ़रत फैलाने के बजाय एकता और सहयोग की कहानियाँ दिखा सकती है। फिल्में, लेख और सोशल मीडिया एकता और साझा मूल्यों की शक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। युवा पीढ़ी समाज का भविष्य है। छात्रों और युवाओं के लिए विशेष संवाद सत्र

इज्जत का हक़ — सिर्फ़ औरत नहीं, हर इंसान का

समाज की नींव समानता और न्याय पर टिकी होनी चाहिए, मगर हकीकत यह है कि सदियों से 'इज्जत' को लेकर एकपक्षीय सोच ने जड़ें जमा ली हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि "औरत की इज्जत" सर्वोपरि है, मानो पुरुष की गरिमा, उसकी भावनाएँ, उसका दर्द और उसका सम्मान कोई मायने ही नहीं रखता। यह सवाल गूँजता है—इज्जत सिर्फ औरत की क्यों? क्या पुरुष की अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? क्या उसकी पीड़ा को केवल इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि वह पुरुष है? यह दोहरा मापदंड न केवल सामाजिक असंतुलन पैदा करता है, बल्कि एक ऐसी दुनिया रचता है जहाँ पुरुष की आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसका सच अनसुना रह जाता है। इज्जत को सिर्फ स्त्री की देह और उसकी शुचिता तक सीमित करना समाज की सबसे बड़ी भूल है। यह सोच पुरुषों के प्रति एक गहरे अन्याय को जन्म देती है, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है, समाज तुरंत उसकी हिमायत में खड़ा हो जाता है। सड़कों पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर हंगामा, और न्याय की माँग—यह सब स्वाभाविक और ज़रूरी है। लेकिन जब पुरुष के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा होती है, तो समाज खामोश क्यों हो जाता है? पुरुषों की पीड़ा को नजरअंदाज करना, उसे मर्दानगी के तमगे से ढक देना, एक खतरनाक परंपरा बन चुकी है। घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) केवल महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि अध्ययन बताते हैं कि भारत में 25-30% विवाहित पुरुष कभी न कभी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। यह हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक भी है—लगातार अपमान, बच्चों से बिछड़ना, झूठे मुकदमों में फँसना, या आर्थिक शोषण। फिर भी, समाज पुरुष से अपेक्षा करता है कि वह चुप रहे, क्योंकि "मर्द को दर्द नहीं होता"। यह सोच पुरुषों को एक ऐसी जेल में कैद करती है, जहाँ उनकी पीड़ा को कोई नाम नहीं मिलता।

यौन शोषण के मामले में भी समाज का रवैया पक्षपातपूर्ण है। आम धारणा है कि यौन उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारत में 53% बच्चे—लड़के और लड़कियाँ दोनों—यौन शोषण का शिकार होते हैं। एनसीआरबी के आँकड़े और स्वतंत्र अध्ययन बताते हैं कि किशोर लड़के और युवा पुरुष भी यौन हिंसा का सामना करते हैं। मगर समाज उनकी पीड़ा को या तो हँसी में उड़ा देता है या चुप कराने की कोशिश करता है। एक पुरुष के यौन शोषण को गंभीरता से न लेना, उसकी इज्जत को ठेस पहुँचाने जैसा है। यह क्रूर विडंबना है कि एक ही अपराध को लिंग के आधार पर अलग-अलग तराजू पर तौला जाता है।

इज्जत को सिर्फ स्त्री की देह से जोड़ना पुरुषों के लिए भी अन्यायपूर्ण है। समाज ने पुरुष की इज्जत को उसकी कमाई, सफलता और "मजबूती" से जोड़ दिया है। अगर वह बेरोजगार है, आर्थिक रूप से कमजोर है, या अपनी पत्नी से कम कमाता है, तो उसकी इज्जत पर सवाल उठने लगते हैं। यह सोच पुरुषों को मानसिक दबाव और अवसाद की गहरी खाई में धकेल रही है। एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में 70% पुरुष थे, जिनमें से अधिकांश पारिवारिक दबाव, आर्थिक तंगी और सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ तले दबे थे। यह आँकड़ा चीख-चीखकर बताता है कि समाज पुरुष से सिर्फ कर्तव्य निभाने की उम्मीद करता है, उसकी भावनाओं को सुनने की नहीं। पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं से तीन गुना अधिक होना इस बात का सबूत है कि उनकी इज्जत और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

झूठे आरोपों का दंश भी पुरुषों की इज्जत को चोट पहुँचाता है। एक झूठा इल्ज़ाम पुरुष की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। चाहे वह अदालत में निर्दोष साबित हो जाए, मगर समाज और मीडिया की नजरों में वह हमेशा संदिग्ध बना रहता है। भारत में दहेज उत्पीड़न कानून (498A) के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जहाँ पुरुषों और उनके परिवारों को बिना सबूत के सालों तक कानूनी और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी, फिर भी समाज में पुरुष की इज्जत को इस तरह की बदनामी से बचाने की कोई चर्चा नहीं होती। यह एकतरफा सोच पुरुषों को असहाय और समाज में हाशिए पर धकेल देती है।

हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ भी इस असमानता को पोषित करती हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री की रक्षा को धर्म से जोड़ा गया है, लेकिन पुरुष की इज्जत और गरिमा की रक्षा को उतना महत्व नहीं दिया गया। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण को इज्जत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभिमन्यु के छलपूर्ण वध को शायद ही सम्मान के दृष्टिकोण से याद किया जाता है। यह प्रवृत्ति इतिहास से लेकर आज तक चली आ रही है, जहाँ पुरुष के दर्द को कमतर आँका जाता है।

इज्जत की परिभाषा को फिर से गढ़ने की जरूरत है। इज्जत न तो स्त्री की देह तक सीमित है, न ही पुरुष की कमाई या ताकत तक। यह हर इंसान की गरिमा, उसकी भावनाओं और उसके अस्तित्व का सम्मान है। समाज को यह समझना होगा कि पुरुष भी इंसान हैं—वे भी रो सकते हैं, उन्हें भी सहानुभूति चाहिए, और उनकी इज्जत का हनन उतना ही गंभीर है जितना किसी और का। स्कूलों, कॉलेजों और परिवारों में बच्चों को यह सिखाना होगा कि सम्मान लिंग पर नहीं, इंसानियत पर आधारित होना चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब सिर्फ महिलाओं का उत्थान नहीं, बल्कि पुरुषों की पीड़ा को भी सुनना और उनकी गरिमा को बराबर महत्व देना है।

सोशल मीडिया और डिजिटल युग में इस मुद्दे को उठाने का बेहतरीन अवसर है। युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं। हमें ऐसी कहानियाँ सामने लानी होंगी, जहाँ पुरुषों ने अपनी पीड़ा को आवाज़ दी और समाज ने उनकी बात सुनी। गैर-सरकारी संगठन और सरकार को मिलकर पुरुषों के लिए भी कानूनी सुरक्षा और काउंसलिंग सेवाएँ शुरू करनी चाहिए। घरेलू हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ पुरुषों के लिए भी नीतियाँ बननी चाहिए, ताकि उनकी इज्जत को भी उतना ही संरक्षण मिले।

राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की तरह, हमें एक राष्ट्रीय लैंगिक समानता पखवाड़ा शुरू करना चाहिए, जहाँ इज्जत को लिंग से परे, इंसानियत के नजरिए से देखा जाए। यह समय है कि हम पुरुषों की चुप्पी तोड़ें, उनकी पीड़ा को सुनें और उनकी इज्जत को उतना ही महत्व दें जितना किसी और की। जब हम यह कह सकें कि "इज्जत हर इंसान की है", तभी हम एक सच्चे समतामूलक समाज की नींव रख पाएँगे। इज्जत का मतलब है सम्मान, और सम्मान हर उस शख्स का हक है जो इस धरती पर साँस लेता है। इस दोहरे मापदंड को तोड़ें और एक ऐसी दुनिया बनाएँ, जहाँ हर इंसान की इज्जत बराबर हो—चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, या कोई और। यह बदलाव न सिर्फ समाज को मजबूत करेगा, बल्कि हर इंसान के दिल में इंसानियत की रोशनी भी जलाएगा।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

धरती का सच और हमारा कल

शम्भू शरण सत्यार्थी

इंसान का इतिहास दो तस्वीरों में बँटा है। पहली तस्वीर—जिसमें इंसान खेतों में अनाज उगाता है, पुल बनाता है, नदियों पर बाँध खड़ा करता है, बीमार का इलाज करता है, और बच्चों को पढ़ाता है। दूसरी तस्वीर—जिसमें वही इंसान धरती के टुकड़े करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हथियार बनाता है, और अपने छोटे स्वार्थों के लिए लाखों की जान लेता है।

हमारी सभ्यता की शुरुआत सहयोग से हुई थी। जब हम शिकारी-फ़सल काटने वाले समाज से आगे बढ़े, तो एक-दूसरे पर निर्भर रहने की आदत बनी लेकिन समय बीतते-बीतते हमने अपनी पहचान को छोटे-छोटे खाँचों में बाँट दिया—जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और देश। अब यह खाँचे दीवारों में बदल गए हैं और उन दीवारों को गिराने की जगह हम उन्हें और ऊँचा कर रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा गाँव। गली के नुक्कड़ पर चायवाले की केतली हमेशा खौलती रहती है।

यहीं एक दिन एक बाहरी आदमी आया। उसने धीरे-धीरे कुछ घरों में बैठना शुरू किया। वह कहता—

"तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी पूजा अलग है। पड़ोसी तुम्हारे भाई नहीं हो सकते।"उनका धर्म अलग है । हम लोगों का धर्म अलग है। हमलोग गाय की पूजा करते हैं, वे लोग उसे काटकर खाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी एकदूसरे धर्म वाले से नफ़रत की बातें करते ।

पहले लोग हँसकर बात टाल देते, लेकिन बीज बो दिया गया था। महीनों में शक की बेल फैल गई। त्योहारों की मिठाई का आदान-प्रदान बंद हो गया। एक दूसरे के पर्व त्योहार पर आना जाना खत्म सा हो गया।

एक दिन किसी छोटी बात पर मारपीट हो गई। गाँव के बीच दीवार खिंच गई।

जो कल तक एक-दूसरे की फसल काटने में मदद करते थे, अब बात तक नहीं करते।

यह कहानी सिर्फ़ उस गाँव की नहीं—यह हर जगह हो रही है।

इंसान ने चाँद पर झंडा गाड़ दिया, मंगल की मिट्टी का नमूना ला लिया, और समुद्र की गहराई में कैमरे उतार दिए लेकिन यही इंसान अगर चाह ले, तो एक बटन दबाकर पूरी धरती को राख में बदल सकता है।

दुनिया में इतने परमाणु हथियार जमा हो चुके हैं कि धरती को सौ बार नष्ट किया जा सकता है। यह वही इंसान है जिसने कभी आग जलाना सीखा था ताकि खाना पका सके।

अब वही आग, बस्तियाँ जलाने में लग रही है। हथियार बनाने की दौड़ ऐसी है कि हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं जबकि लाखों बच्चे भूख से मरते हैं।

ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 1% आबादी के पास 90% संपत्ति है। मतलब, अगर 100 लोगों का एक गाँव हो तो सिर्फ़ एक आदमी के पास सब खेत, कुएँ और गोदाम हों और बाकी 99 लोग रोटी के लिए तरसें।

एक रात मैंने अपने आँखों से देखा—एक होटल के पीछे, जहाँ बचे खाने के डिब्बे फेंके जा रहे थे, एक माँ अपने बच्चे को उस जूठन से निकाल कर अपने खुद खा रही और बच्चे को खिला रही है।

यह सिर्फ भूख की कहानी नहीं, यह इंसानियत की नाकामी है।

इतिहास गवाह है—जंग में जीत कोई नहीं पाता। हार हर किसी की होती है।

1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। पलक झपकते ही शहर खाक हो गया। जो बचे, उनके शरीर जल गए और आने वाली पीढ़ियाँ विकलांग पैदा हुईं।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद सुलझाते हैं, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जहाँ बच्चों को डरकर सोना न पड़े। लेकिन शांति के लिए हिम्मत चाहिए—जंग छेड़ना आसान है, शांति बनाना कठिन।

हममें से ज़्यादातर लोग अपने-अपने छोटे फायदे में उलझे रहते हैं। कोई पद के लिए लड़ रहा है, कोई ठेके के लिए, कोई मुनाफ़े के लिए।

इन छोटे स्वार्थों में हम भूल जाते हैं कि इंसान होने का एक बड़ा मक़सद भी है—धरती को समझना, उसके रहस्यों को जानना, और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सँभालकर रखना।

विज्ञान का मतलब केवल मोबाइल, कार या मशीन बनाना नहीं है। विज्ञान का असली मक़सद है—प्रकृति को समझना और इंसानियत की भलाई करना।

पहले झूठ परोसो, फिर माफी मांग लो, ''सीएसडीएस'' की विश्वसनीयता पर संदेह !

देश में 'वोट चोरी' के नाम पर राजनीतिक बवंडर खड़ा करने वाले सीएसडीएस (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज) के संजय कुमार और कॉन्ग्रेस के राहुल गाँधी समेत कई लोगों के खिलाफ दिल्ली में शिकायत की गई है। फर्जी आँकड़ों के आधार पर ये खेल शुरू करने वाले संजय कुमार अब निशाने पर आ चुके हैं।

इस बीच, सीएसडीएस को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाली सरकारी संस्थान- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने सीएसडीएस पर सवाल उठाए हैं और शो कॉज नोटिस जारी किया है। आईसीएसएसआर ने सीएसडीएस पर फर्जी डेटा पेश करने और चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुँचाने का भी आरोप लगाया है। वहीं, सीएसडीएस की विदेशी फंडिंग खासकर जर्मनी की कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन से मिलने वाले करोड़ों रुपए अब जाँच के घेरे में हैं।

जानकारी के अनुसार यह विवाद 17 अगस्त 2025 को तब शुरू हुआ जब सीएसडीएस के संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि नासिक वेस्ट का वोटर संख्या लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक 47.38 प्रतिशत बढ़ गई जबकि हिंगणा में 42.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। साथ ही, रामटेक और देवलाली में वोटर संख्या में 40 प्रतिशत की कमी आई लेकिन 19 अगस्त को संजय कुमार को कथित तौर पर अपनी गलती का अहसास हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफी माँगी। उनका कहना था कि उनकी टीम ने डेटा की पंक्तियों को गलत पढ़ लिया था लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और फर्जी आँकड़े सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैल चुके थे। असली डेटा देखें तो नासिक वेस्ट में वोटर संख्या में सिर्फ 6 प्रतिशत और हिंगणा में 5.9 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि रामटेक और देवलाली में 3-4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

इस घटना से नाराज होकर 19 अगस्त को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक बयान जारी किया। शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली आईसीएसएसआर सीएसडीएस को फंडिंग देने वाली मुख्य संस्था है। आईसीएसएसआर के बयान में कहा गया कि सीएसडीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी (संजय कुमार) ने गलत डेटा पेश किया जो बाद में वापस लेना पड़ा। इसके अलावा, सीएसडीएस ने चुनाव आयोग के एसआईआर (सार्वजनिक जानकारी अभ्यास) को गलत तरीके से पेश करके मीडिया स्टोरीज छापीं।

आईसीएसएसआर ने कहा कि चुनाव आयोग भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की रीढ़ है और इसके सम्मान को ठेस पहुँचाना गंभीर अपराध है। उन्होंने सीएसडीएस पर डेटा से छेड़छाड़ और गलत नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया जो उनके अनुदान नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह घटना संस्थान और चुनाव प्रक्रिया दोनों की गरिमा को ठेस पहुँचाती है।

इसी बीच वकील विनीत जिंदल ने 19 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी। उनकी शिकायत में राहुल गाँधी (विपक्ष के नेता), संजय कुमार (सीएसडीएस) और कई अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए। जिंदल का कहना है कि इन लोगों ने फर्जी डेटा फैलाकर जनता में अशांति फैलाई और सरकार के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि यह डेटा लोकसभा चुनावों को लेकर गलत था और चुनाव आयोग की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। जिंदल ने अपनी शिकायत में लिखा कि ये लोग सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए झूठी खबरें फैला रहे हैं, जिससे जनता का भरोसा लोकतंत्र पर कमजोर हो रहा है। उन्होंने माँग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और जाँच शुरू की जाए।

अब सवाल उठता है कि सीएसडीएस को फंडिंग कहाँ से

मिलती है? आईसीएसएसआर सीएसडीएस का मुख्य फंडर है, जो सरकार के जरिए चलता है। लेकिन इसके अलावा सीएसडीएस को विदेशी फंडिंग भी मिलती है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सीएसडीएस की वेबसाइट और विदेशी योगदान की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई देशों और संगठनों से पैसा आता है। इनमें फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन (अमेरिका), आईडीआरसी-कनाडा, डीएफआईडी (यूके), नॉराड (नॉर्वे), ह्यूलेट फाउंडेशन और जर्मनी की केएएस जैसी एजेंसियाँ शामिल बताई जा रही हैं। इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान की कुछ एनजीओ से भी डोनेशन मिलते हैं।

इसके अलावा अतीत में जाकर देखें तो साल 2016 से अगले कई सालों तक कनाडा की संस्था की तरफ से हर साल करोड़ों की धनराशि लगातार मिलती रही। भारत सरकार ने एनजीओ की आड़ में विदेशी धन के प्रवाह को रोकने के लिए जब कदम उठाए, तो इसका असर सीएसडीएस की फंडिंग पर भी पड़ा। साल 2016 और 2025 के आँकड़ों में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है।

सीएसडीएस को जो विदेशी फंडिंग होती है उसको लेकर आरोप है कि यह पैसा हिंदू समाज को जाति के आधार पर बाँटने और गलत नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए सीएसडीएस के लोकनीति प्रोग्राम में हिंदुओं को ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण में बांटकर वोटिंग पैटर्न की रिपोर्ट छापी जाती है जो अखबारों में सुर्खियाँ बनती हैं लेकिन मुसलमानों की अंदरूनी जातीय दरारों पर चुप्पी साध ली जाती है। कई लोग इसे साजिश मानते हैं और कहते हैं कि सीएसडीएस का मकसद हिंदू समाज को तोड़कर कॉन्ग्रेस जैसे दलों को फायदा पहुँचाना है।

जानकारों के अनुसार आईसीएसएसआर ने साफ कर दिया है कि सीएसडीएस का यह व्यवहार उनके नियमों का उल्लंघन है। शो कॉज नोटिस के बाद अगर सीएसडीएस संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता, तो फंडिंग रोकने की नौबत आ सकती है। यह कदम न सिर्फ सीएसडीएस के लिए बड़ा झटका होगा बल्कि इस बात की भी जाँच शुरू हो सकती है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर साबित हो जाता है कि विदेशी पैसा किसी खास राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

जानकारों की माने तो सीएसडीएस को आईसीएसएसआर के शो कॉज नोटिस और विनीत जिंदल की एफआईआर से साफ है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। चुनाव आयोग की साख बचाने और फर्जी डेटा से नुकसान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अगर सीएसडीएस दोषी पाया जाता है, तो न सिर्फ उसकी फंडिंग पर असर पड़ेगा, बल्कि उसके शोध कार्यों पर भी सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग की जाँच शुरू होने से सीएसडीएस को और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जनता के लिए भी यह सब एक सबक है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जाँच लेनी चाहिए।

यह पूरा मामला सीएसडीएस, आईसीएसएसआर और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। फंडिंग को लेकर उठे सवाल, फर्जी डेटा का विवाद, और एफआईआर सब कुछ मिलाकर यह दिखाता है कि शोध संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आईसीएसएसआर का कड़ा रुख और जिंदल की शिकायत से उम्मीद है कि सच सामने आएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी जिससे भविष्य में कोई भी संस्थान भ्रामक डाटा या सूचना सार्वजनिक करने से पहले सोचे।

-रामस्वरूप रावतसरे

नगड़ी जमीन पर हल चलाने के पूर्व ही चंपाई हाउस अरेस्ट, सड़कें बेरिकेटेड

भाजपा नेता आहुत विरोध में शिबू सोरेन का मुखौटा पहने पहुंचे थे आदिवासी, देवेंद्र महतो ने चलाया हल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, सरकार द्वारा नगड़ी में रिम्स अस्पताल २ के लिए जमीन अधिग्रहण का पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के विरोध का नजारा कुछ अलग था . आदिवासी मुलवासियों के खेती-बाड़ी की जमीन को लेकर की गयी चंपाई की मौजूदा राजनीति के इस नये आन्दोलन के दिन खराब मौसम के बावजूद उनके बेटे तथा अन्य कार्यकर्ताओं को स्थल पर जाने से पुलिस ने विभिन्न जगहों पर रोक लिया . इसके बाबजूद जो लोग पहुंचे पुलिस से झगड़ते हुए उन्होंने हल जोता, रोपाई की उधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को रविवार सुबह उनके रांची स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था . यह कार्रवाई सदर डीएसपी की अगुवाई में की गई. बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन रविवार को नगड़ी में चल रहे रिम्स-2 जमीन विवाद को लेकर हल चलाने और प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया. प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया. चंपई सोरेन ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें घर से बाहर जाने से रोका गया है.चंपाई सोरेन नगड़ी नहीं पहुंच पाये.

भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व विधायक रामकुमार पाहन और गंगोत्री कुजूर वहां पहुंचीं, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो हल-बल लेकर नगड़ी पहुंच गये हल भी चलाया।

इस पर चंपाई सोरेन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने पर मुझे नजरबंद करना अलोकतांत्रिक है. इसके अलावा, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है. बाबूलाल सोरेन भी इसी प्रदर्शन में भाग लेने रांची जा रहे थे. बाबूलाल सोरेन को तमाड़ में डिटेन किया गया. सोरेन ने 19 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया है और क्षेत्र में सुरक्षा बाड़ लगाकर किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है।

रांची में करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले प्रशासन ने शनिवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी और राज्य की राजधानी के नगड़ी इलाके में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया. किसानों, भूमि मालिकों और 20 से अधिक आदिवासी समूहों ने रविवार को उस स्थल पर 'हल जोतो, रोपा रोपो' विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी , जहां एक हजार करोड़ रुपये की रिम्स 2 अस्पताल परियोजना प्रस्तावित है. राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा केंद्र राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के विस्तार को रिम्स 2 नाम दिया गया है.

आज रांची में बेरिकेडिंग लगाकर भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गयी थीं जहां विभिन्न जिलों से रांची पहुंच रहे लोगों को रोका गया था । इसके बाबजूद लोग पहुंचे जहां पुलिस ने आंसु गैस के गोले भी दागे गये ।इसके बाबजूद लोगों ने नगड़ी के आन्दोलन जमीन पर धान रोपाई की ।बाड को गिरा दिया।

लोकतांत्रिक शुचिता के ज़रूरी है जेल से सरकार पर संविधान का अंकुश

हरीश शिवननी

इस बार सांसद का मानसून सत्र दो विशेष कारणों से याद रखने योग्य है। संसद अपने तयशुदा कार्यक्रम 120 घंटे की बजाए महज 37 घन्टे ही काम कर पाई। दूसरा, सत्र के अंतिम दिन पेश किए गए प्रस्तावित130 वें संविधान संशोधन की वज़ह से मचा बवाल।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। बिल कहता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर लगातार 30 दिन तक जेल में बंद रहता है, और आरोप ऐसा है कि उसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो उसे पद से हटना पड़ेगा या उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239AA में बदलाव करेगा।

यह प्रस्ताव फिलहाल संसदीय समिति के विचाराधीन है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस,राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों का इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया है। इन दलों का आरोप है कि सरकार यह संशोधन विरोधी दलों को राजनीतिक साजिश में फंसाने के उद्देश्य से लाई है। दूसरी तरफ़ सरकार का दावा है कि इस विधेयक से राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी। भारतीय संसदीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले जनप्रतिनिधियों का बढ़ता आंकड़ा भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरों में से एक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की साझा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान 18वीं लोकसभा में 46 फीसदी के साथ ये संख्या 251 है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 102 और 191 दोषसिद्धि पर सांसदों-विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं लेकिन संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद हटाया जा सके। इस कमी के कारण भ्रष्टाचार और अनैतिकता को बल मिलता है। प्रस्तावित विधेयक ठीक यही करता है- यह गिरफ़्तारी और दोषसिद्धि के बीच के खालीपन को भरता है, संवैधानिक शिष्टता के सिद्धांत और लोकतांत्रिक शुचिता को कायम रखता है। दरअसल इस विधेयक को लाने के मूल में स्वयं विपक्ष ही जिम्मेदार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पद पर रहते हुए विभिन्न आरोपों में गिरफ़्तार होकर जेल तो गए लेकिन पद पर बने रहे। बाद में यही हालात तब बने जब शराब घोटाले में गिरफ़्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे लेकिन इस्तीफ़ा देने की बाजार 'जेल से ही सरकार' चलाने लगे और जेल को राजनीतिक कार्यालय में बदल दिया। यह भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का पतन काल था। इनसे पहले बिहार के लालूप्रसाद यादव, तमिलनाडु की जयललिता और एम करुणानिधि, मध्यप्रदेश की उमा भारती और झारखंड के मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन भी विभिन मामलों में गिरफ़्तार हुए लेकिन उन्होंने गिरफ़्तारी के साथ ही इस्तीफ़ा दे दिया था। दरअसल किसी मामले में दोषी सिद्ध सांसदों, विधयकों और मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की शुरुआत परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने ही की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 के एक फैसले कहा था कि किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष या अधिक सजा होने पर उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार इस फैसले को ओवर राइड करने के उद्देश्य से 24 सितंबर 2013 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अध्यादेश ले आई, इसका उद्देश्य दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य घोषित होने से बचाना था। इससे खफ़ा होकर राहुल गांधी ने 27 सितंबर 13 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अध्यादेश की कॉपी को 'कम्प्लीट नॉनसेंस' बताते हुए कहा कि इसे ₹फाड़कर फेंक देना चाहिए₹। ग़ौरतलब है कि तब कांग्रेस सत्ता में थी और यह संदेश गया था कि राहुल गांधी राजनीति में शुचिता लाने के प्रबल पक्षधर हैं लेकिन वही राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए अब प्रस्तावित 130वें संशोधन के ख़िलाफ़ मुखर हो गए हैं। बी आर अंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि भारत में लोकतंत्र न केवल संवैधानिक प्रावधानों पर बल्कि पद धारण करने वालों की नैतिक संरचना पर निर्भर करेगा। ₹एक संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है अगर इसे काम करने के लिए बुलाए गए लोग अच्छे हों।" प्रस्तावित 130वां संशोधन इसी सिद्धांत को संस्थागत बनाता है। यह विधेयक यही सुनिश्चित करता है कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जाएंगी और नहीं चलनी चाहिए।

विरोधियों का तर्क है कि इसका दुरुपयोग विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष के इस दावे में दम नहीं है। यह विधेयक सभी दलों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह भाजपा, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री कार्यालय भी कानून के दायरे में रखा गया है। यह प्रावधान केवल अस्थायी हटाना सुनिश्चित करता है। एक बार रिहा होने के बाद, मंत्री को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। लोकतंत्रों को न केवल चुनावों से बल्कि उनकी संस्थाओं की ईमानदारी से आंका जाता है। 'मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हैं' जैसे वाकये भारत की लोकतांत्रिक छवि को कमजोर करते हैं। प्रस्तावित कानून सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा।

अखिलेश जैसे का चेहरा बेनकाब करने के लिए धन्यवाद योगी और धन्यवाद अखिल !

सुनील बाजपेई

कानपुर। विषकन्याओं यानी कमसिन लड़कियों के माध्यम लोगों के खिलाफ बलात्कार और छेड़खानी आदि के फर्जी मुकदमे में दर्ज करा रंगदारी, ब्लैक मेलिंग और अवैध कब्जों में सफलता के बदले कई हजार करोड़ की नामी - बेनामी, चल - अचल संपत्ति अर्जित करने वाले जेल भेजे गए वकील अखिलेश दुबे के देशव्यापी कारनामों का खुलासा लगातार जारी है। कानपुर के साथ ही देश के और भी कई राज्यों में दर्जनों को शिकार बना चुका यह देश का एक मात्र पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय गिरोह है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में विषकन्याएं यानी लड़कियां भी शामिल थी। यह देश का पहला ऐसा गिरोह है ,जिससे बड़ा प्रभावशाली, जिससे बड़ा ऊंची पहुंच और पकड़ वाला गिरोह आज तक पूरे देश में प्रकाश में नहीं आया , जिसकी असली वजह लाखों करोड़ों की चल नामी बेनामी संपत्ति के रूप में भारी लाभ भी उठाने वाले कानून व्यवस्था जैसे पद वाले के साथ कई आईपीएस ,आई ए एस, पीपीएस, पीसीएस समेत विभिन्न विभागों के भी कई अधिकारियों, पत्रकारों, नेताओं और वकीलों आदि द्वारा गिरोह को संरक्षण और सहयोग रहा।

यही वजह है कि ऐसे प्रभावशाली और मजबूत पकड़ वाले अखिलेश दुबे जेल भेज कर गिरोह का भंडाफोड़ करना बिल्कुल असंभव ही था। लेकिन इस असंभव को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में संभव कर दिखाया अब डीजी भी बन चुके निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य शैली के भगवान और भाग्य यानी कर्म भरोसे रहने वाले कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की विशुद्ध ईमानदारी ,कर्तव्य निष्ठा और निडरता ने। जिसने आतंक से मुक्ति के साथ केवल अखिलेश दुबे का समाज विरोधी असली अपराधी माफिया चेहरा ही बेनकाब नहीं किया, बल्कि ना जाने कितने लोगों को भविष्य में गिरोह शिकार होने से भी बचा लिया। जिससे यह भी प्रमाणित हो गया कि पुलिस कमिश्नर के रूप में अखिल कुमार जैसा अभूतपूर्व विशुद्ध ईमानदार, अखिल कुमार जैसा

अभूतपूर्व निडर ,अखिल कुमार जैसा जुझारु, अखिल कुमार जैसा नेतृत्व कुशल ,अखिल कुमार जैसा कठोर परिश्रमी, और अखिल कुमार जैसा व्यवहार कुशल कानपुर को इसके पहले ना तो कभी मिला था और ना ही इसके बाद कभी मिलने की संभावना है। यही वजह है कि कानपुर उनके व्यक्तित्व और जनहित में उनके कृतित्व को कभी भूलेगा भी नहीं।

यह भी सच है कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार कानपुर के पुलिस कमिश्नर नहीं होते तो भी अखिलेश दुबे या अवनीश दीक्षित जैसे गिरोह का भंडाफोड़ कभी भी और कदापि नहीं हो पाता। इसीलिए जनहित में इस अभूतपूर्व सफलता के लिए भूतो न भविष्यति की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले एक तरह से दुर्लभ के साथ ही अद्वितीय ईमानदार और अद्वितीय निर्भीक डीजी बन चुके पुलिस कमिश्नर वरिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार ही नहीं बल्कि यूपी को अपराधी माफियाओं से मुक्ति के अपने संकल्प में सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोटिशः धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। इसी क्रम में अखिलेश को जेल भेजने में किसी भी तरह की अड़चन नहीं पैदा होने देना भी निःसंदेह पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की ईमानदारी, निडरता और उनकी कर्तव्य निष्ठा का मुख्यमंत्री योगी द्वारा किया गया सम्मान भी है ,नहीं तो जिस तरह से कानून व्यवस्था जुड़े बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी भी अखिलेश दुबे के पक्ष में दबाव बना रहे थे। अगर योगी आदित्यनाथ की जगह और कोई मुख्यमंत्री होता तो वह सभी अपने इरादे में सफल भी अवश्य हो जाते। और यही सत्य वरिष्ठ आईपीएस अखिल कुमार के बारे में भी है। मतलब अगर विशुद्ध ईमानदार और निडरता के भी पर्याय अखिल कुमार के स्थान पर कोई दूसरा पुलिस कमिश्नर होता तो वह दस पांच करोड़ नहीं ,10 - 5 लाख में ही बिक जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ ,क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को विश्वास है कि संसार संचालक ईश्वर समय आने पर अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही देता है। और वह इसके लिए जिन्हें अपना माध्यम बनाता है। वह जनहित में अपना कर्तव्य भी संपूर्ण यानी अखिल ही निभाता है। जनहित में ऐसे संपूर्ण मतलब अखिल को कोई खरीद नहीं पाता है, क्योंकि खरीदने की हर संभव कोशिशों के खिलाफ विशुद्ध ईमानदारी का नाम अखिल है। दबाव में नहीं झुकने वाली निडरता का नाम भी अखिल है। और अगर यह सच नहीं होता तो अखिलेश या अवनीश जैसे मानव शरीर धारी कलयुगी राक्षसों का चेहरा कभी बेनकाब हो ही नहीं पाता।

जेल भेजने के पहले तक लोगों को यह भी यकीन था कि धरती पर ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ ,जो अखिलेश दुबे का बाल बांका कर सके, लेकिन उसे उनके कर्मों का फल आसमान में नहीं बल्कि इसी धरती पर ही इसी लिए मिला, क्योंकि जब जन्म धरती पर। मृत्यु धरती पर। और सारे अच्छे - बुरे कर्म धरती पर ,तो फिर इंसान उनका फल भी आसमान में नहीं धरती पर ही पाता हैं ,जिसके लिए ही परमेश्वर योगी ,मोदी ही नहीं आई पी एस अखिल कुमार भी बन जाता है। शायद यही वजह है कि इस सफलता का एक ही राशि वालों से भी नाता है ,जिसका क्रम आदित्यनाथ ,अखिल कुमार ,अवनीश अखिलेश भी साफ नजर आता है। मतलब अशुभ अवनीश अखिलेश के शमन के लिए शुभ आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री और अखिल कुमार पुलिस कमिश्नर को परमेश्वर ही अपना माध्यम बनाता है और जिसकी वजह से ही अतीक, मुख़्तार और विकास दुबे से भी बड़े, अतीक, मुख़्तार और विकास दुबे से भी शातिर तथा अतीक, मुख़्तार और विकास दुबे से भी ऊंची पहुंच वाले प्रभावशाली खतरनाक अखिलेश दुबे जैसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ भी हो जाता है।

ईचागढ़ में ज्योति शंकर सतपथी का अवैध बालू पर पैनी नजर

परिवहन विशेष न्यूज

सरायकेला : बालू का अवैध कारोबार का पर्याय बना सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ , कुकड़ु , बंगाल सीमा क्षेत्र में उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी का सक्रियता दिखाई पड़ रहा है । आज ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर में औचक निरीक्षण किया गया जहां अवैध बालू से लदा हाईवा की जांच हुई ।

निरीक्षण के क्रम में बालू खनिज लदे वाहनों को रोककर उनके परिवहन संबंधी कागजात एवं खनिज मात्रा की विधिवत जांच की गई। इस दौरान किसी भी वाहन द्वारा अवैध खनिज परिवहन का मामला सामने नहीं आया। सभी वाहन आवश्यक कागजातों के साथ वैध रूप से खनिज का परिवहन करते पाए गए।

जिला खनन पदाधिकारी श्री ज्योति शंकर सतपती ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के औचक निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे, ताकि अवैध खनन एवं खनिज परिवहन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध खनन अथवा खनिज परिवहन की जानकारी प्राप्त हो तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएँ

ढेंकनाल में एसपी कार्यालय परिसर में महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, 2 सब-इंस्पेक्टर निलंबित

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : ढेंकनाल में पुलिस थाने से न्याय न मिलने पर एक महिला द्वारा एसपी कार्यालय परिसर में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद, ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दो सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। ये सब इंस्पेक्टर सदर थाने की सब-इंस्पेक्टर रेजालिन मिंज और टाउन थाने के सब-इंस्पेक्टर उत्कल विजय मोहंती हैं। इन दोनों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है ।पुलिस ने महिला को पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास करते हुए पकड़ा। यह खबर ढेंकानाल सदर थाना अंतर्गत अनक्रांतिपुर गाँव से आई है। अपने रिश्तेदारों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित महिला बार-बार सदर थाना और टाउन थाना के चक्कर लगा चुकी थी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।

आखिरकार वह हार गई। आज वह अपने साथ प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल और डीजल लेकर आई और एसपी कार्यालय परिसर में आत्महत्या करने की कोशिश की। सदर और टाउन थाना के अधिकारियों ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, इस पर ढेंकानाल एसपी ने दोनों थानों के अधिकारियों को कार्यालय में बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

रांची का तस्कर इरफान अंसारी ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची ,रांची सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला इरगु रोड इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर इरफान अंसारी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है।

साथ ही उसके पास से नशीली ड्रग्स की बिक्री से अर्जित साढ़े 33 हजार रुपये भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी कृष्णा कुमार साहू के बयान पर इस मामले में केस हुआ है।

पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली कि इरफान अंसारी अपने घर के पास ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री कर रहा है। पुलिस की टीम आरोपित के घर पहुंची तो आरोपित भागने लगा। लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 25 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023